

<div>● वर्ष-6</div>
<div>● अंक-80</div>
<div>रायपुर, शुक्रवार</div> <div>30 अक्टूबर 2026</div>
<div>● पृष्ठ-8</div>
<div>● मूल्य-३ रु.</div>

॥ संगछध्वम् संवदध्वम् ॥

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>>
बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा...



महाराष्ट्र महायुति के भीतर दरार! एनडीए 15 सीटें जीती, इंडि को 10 सीटें मिली

एमएलसी चुनाव में हार पर भाजपा ने शिंदे शिवसेना को घेरा, क्या आरोप लगाए?

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में आपसी मतभेद सामने आ गए हैं। पांच सीटों पर हुए चुनाव में विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने तीन सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को केवल दो सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद भाजपा ने सहयोगी शिवसेना पर सहयोग नहीं करने और गठबंधन की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इस विवाद ने महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के भीतर राजनीतिक खींचतान को सामने ला दिया है।

महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने आरोप लगाया कि शिवसेना ने पुणे और नागपुर की सीटों पर गठबंधन के साथ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप को आखिरी समय में समर्थन देने से महायुति की एकजुटता को नुकसान पहुंचा। बन के मुताबिक, शिवसेना के इस फैसले से गठबंधन के सहयोगियों के बीच तालमेल प्रभावित हुआ। उन्होंने सोशल



मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अगर शिवसेना ने भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का साथ दिया होता, तो गठबंधन सभी पांच सीटें जीत सकता था।

भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर गठबंधन के हितों के बजाय एक सीट पर ध्यान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुणे में एक सीट के लिए अलग-अलग रुख अपनाने से सहयोगी दलों को नुकसान हुआ और गठबंधन तीन अतिरिक्त सीटें जीतने का अवसर गंवा बैठा। बन ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार ने छत्रपति संभाजीनगर में राकांपा के खिलाफ प्रचार किया, जिससे गठबंधन की संभावनाओं पर असर पड़ा। हालांकि, ये आरोप भाजपा नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। दिए गए विवरण में शिवसेना की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये ने भी चुनाव नतीजों की समीक्षा करने की मांग की।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब गठबंधन के पास पांचों सीटें जीतने का अवसर था, तो वह केवल दो सीटों पर क्यों सिमट गया। उन्होंने कहा कि महायुति के सभी घटक दलों को मिलकर विचार करना चाहिए कि चुनाव में कहां कमी रह गई। भाजपा नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी इन नतीजों के लिए गठबंधन के भीतर बेहतर तालमेल की कमी को जिम्मेदार मान रही है। महाराष्ट्र में महायुति में भाजपा, शिवसेना और राकांपा शामिल हैं।

23 अक्टूबर को पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था। इनमें पुणे स्नातक सीट पर राकांपा (शरदचंद्र पवार) की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख-जाधव ने जीत दर्ज की। नागपुर स्नातक सीट कांग्रेस के अभिजीत वंजारी के खाते में गई। छत्रपति संभाजीनगर यानी मराठवाड़ा स्नातक सीट पर भी राकांपा (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार ने जीत हासिल की।

नई दिल्ली। चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प रहे हैं। 23 अक्टूबर को मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना का दौर शुरू हुआ। विधान परिषद की 28 सीटों में अब तक आए नतीजों/रुझानों को देखा जाए तो सामने आता है कि भाजपा और उसकी समर्थित पार्टियों वाले एनडीए ने कुल 15 सीटें जीती हैं। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट अन्य और दो निर्दलीयों के पास आती दिख रही हैं।

विहार में क्या बदला?

बिहार विधान परिषद चुनाव की आठ सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 27 अक्टूबर को गणना शुरू हुई तो 29 अक्टूबर को अब जाकर खत्म हुई। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के नीरज कुमार ने अपना कब्जा बरकरार रखा। उन्होंने राजद के दिलीप पटेल को पराजित किया और लगातार चौथी बार इस सीट से विधान पार्षद चुने गए। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के निवर्तमान विधान पार्षद डॉ. मदन मोहन झा को 324 मतों से हराया। यह मुकाबला बेहद करीबी रहा। इस जीत के साथ जन सुराज ने बिहार विधान परिषद में अपना खता खोला।

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा को 594



मतों से हराया। इस सीट पर पहले भाकपा के संजय कुमार सिंह विधान पार्षद थे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने अपनी सीट बरकरार रखी। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के डॉ. एनके यादव ने जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने राजद के नीतेश यादव को 10,026 मतों से हराया।

महाराष्ट्र में क्या बदला?

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों (तीन स्नातक और दो शिक्षक) के परिणामों में विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने तीन सीटें और सत्तारूढ़ महायुति ने 2 सीटें जीती हैं। अजित पवार की राकांपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) दोनों में से किसी भी दल को इन चुनावों में सफलता नहीं मिली (0 सीट)। औरंगाबाद में अजित पवार गुट के निवर्तमान एमएलसी सतीश चव्हाण अपनी सीट हार गए।

भारत में होगा टाइप-25 जापानी मिसाइल का परीक्षण

नई दिल्ली। जापान जल्द ही अपनी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने वाला है जिसका नाम है टाइप 25 एंटीशिप मिसाइल। लेकिन इस मिसाइल का परीक्षण जापान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीं पर हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर जापान को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जापान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जल्द ही उनकी सेना भारत की धरती से मिसाइलों का टेस्ट करेगी जिसमें टाइप 25 एंटीशिप मिसाइल शामिल है। मिसाइलों के साथ अटैक ड्रोन का परीक्षण होगा। हालांकि अब तक जापान की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन



मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ओडिशा के चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप से जापान अपने घातक हथियारों का परीक्षण कर सकता है। सवाल है जापान को भारत में मिसाइल टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों वो अपने

हथियारों का टेस्ट भारत में कर रहा है? तो बता दें जापान घनी आबादी वाला एक छोटा सा देश है जिसके पास लाइव फायर टेस्ट की जमीन नहीं है जिससे लॉन्च हथियारों का टेस्ट संभव नहीं है। ऐसे में जापान ने बतौर क्लाइमैंबर भारत पर भरोसा जताया है और मिसाइल लॉन्च करने की संभावनाओं के लिए अपने अधिकारियों को भारत भेजा है ताकि वो अपने विध्वंसक हथियारों का टेस्ट कर सकें।

गौर करने वाली बात यह है कि जिस टाइप 25 एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट जापान करेगा उसे बनाने का मकसद चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। दरअसल जापान

पूर्वी एशिया में हजारों द्वीपों से बना एक देश है। इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समंदर है और मौजूदा वक्त में जापान के तीन बड़े प्रतिद्वंदी देश हैं। पहला चीन, दूसरा नॉर्थ कोरिया और तीसरा रूस। जहां चीन और जापान के बीच अमेरिका को लेकर तनातनी है तो वहीं रूस के साथ जापान का पुराना सीमा विवाद है और नॉर्थ कोरिया से तनाव की वजह पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रमों से पेसिफिक रीजन में खलबली मचाए हुए हैं जो कि जापान के सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बना हुआ है।



राज्यपाल डेका से एयर ऑफिसर कर्माडिंग नंदा कुमार बाला ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में एयर कमोडोर, एवं एयर ऑफिसर कर्माडिंग हेड क्राटर एंटी नक्सल टास्क फोर्स नंदा कुमार बाला ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कैप्टन वैभव विशाल, जीपी कैप्टन अभिजीत कुमार, सीडीआर प्रियांशु, स्का.लीडर अर्किता सिंह, स्का. लीडर विनय पाठक, लेफ्टिनेंट शशांक, लेफ्टिनेंट साई अक्षय भी उपस्थित थे।

बांग्लादेश : पूर्व वायु सेना अधिकारी की मौत पर सवाल

नई दिल्ली। ढाका में बुधवार को तुराग नदी से बांग्लादेश वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी का शव बरामद किया गया। उनके परिवार ने एक दिन पहले ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट के लापता होने की सूचना दी थी। इसी बीच जमात-ए-इस्लामी के महासचिव मिया गुलाम ने पूर्व वायु सेना अधिकारी तहसीफ सौरी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की बांग्लादेशी मीडिया की खबरों के अनुसार, स्थानीय लोगों की ओर से इमरजेंसी कॉल किए जाने के बाद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तहसीफ सौरी का शव टोंगी बंदर घाट इलाके से बरामद किया गया। अधिकारी की पहचान उनके मोबाइल फोन और कलाई घड़ी मिलने के बाद हो सकी। डेली स्टार से बातचीत में कान्ट्रेबल रकीब ने बताया कि मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। यह जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगी। प्रोथोम आलो के मुताबिक, सौरी अपने परिवार के साथ उत्तरा के सेक्टर 18 स्थित एक फ्लैट में रहते थे। अगस्त 2024 में हिसक विरोध प्रदर्शनों के बीच, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका से रवाना होने के एक वीडियो से कथित संबंध के कारण, सौरी की मौत की खबर पूरे बांग्लादेश में चर्चा का विषय बनी हुई है।

दुर्गा पूजा पास घोटाला: यूनेस्को के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी

कोलकाता । कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और गायक से राजनेता बने इंद्रनील सेन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की सात धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन्हें बुधवार को यूनेस्को-मान्यता प्राप्त उत्सव दौरों से जुड़े, दुर्गा पूजा के कथित फर्जी पास घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। शहर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगाए गए आरोपों में धारा 316 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 336(2) और 336(3) (धोखाधड़ी के लिए जाली दस्तावेज बनाना), धारा 338 (कीमती प्रतिभूतियों और अन्य विशिष्ट दस्तावेजों में जालसाजी), धारा 318 (धोखाधड़ी), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), और धारा 340(2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली बताकर इस्तेमाल करना) शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि 2022 से 2025 के बीच मास आर्ट सोसाइटी के जरिए यूनेस्को और दुर्गा पूजा समारोहों के नाम पर कई करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं की गईं। मास आर्ट सोसाइटी सेन की पत्नी मधुछंदा सेन के स्वामित्व वाली एक कॉर्पोरेट संस्था है। सूत्रों ने आगे बताया कि जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत भी मिले हैं कि पूर्व मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यूनेस्को के नाम पर विभिन्न संगठनों से बड़ी रकम निकाली थी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

प्रमुख समाचार

30 अक्टूबर को किसानों के खाते में आएंगे 2000

नई दिल्ली। दीवाली से पहले, केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इस योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी। इस किस्त के तहत, पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। किस्त जारी होने की तारीख हाल ही में योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई है। उम्मीद है कि लाभार्थियों को दीवाली से पहले यह आर्थिक सहायता मिल जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे किस्त जारी होने से पहले अपना लाभार्थी स्टेटस चेक कर लें और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें। अधिकारियों के अनुसार, अगर ई-चुष्टि अधूरी है या बैंक खाते के विवरण और जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, तो भुगतान रुक सकता है। पीएम के एक क्लिक करते ही देश के 9.34 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,680 से अधिक की राशि का हस्तांतरण होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4482.19 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के (23वीं किस्त तक) 1,03,461.76 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।

1 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त सभा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कथित वोट चोरी के विरोध में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त सभा बुलाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह

लड़ाई हर भारतीय के चुनने के अधिकार की रक्षा के लिए है। एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने कहा कि रविवार को दोपहर 12.30 बजे होने वाली इस सभा में विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर खड़ा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदान को लेकर जो चिंताएं हैं, उनके जवाब मिलने चाहिए। उन्होंने लिखा, रविवार, 1 नवंबर को इंडिया रामलीला मैदान में एकजुट होकर खड़ा होगा।वोट चोरी के खिलाफ यह लड़ाई हर भारतीय के चुनने के अधिकार की रक्षा करने की लड़ाई है। बंगाल और अन्य राज्यों में हुई वोट लूट पर जवाब चाहिए, खामोशी नहीं! चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंताएं जताते हुए, बनर्जी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों , वोटर डेटा, मतदाता सूची और वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने छात्रों,

दिल्ली में पटाखे बैन? सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

नई दिल्ली। त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने को लेकर दिए गए निर्देशों को लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्व्यूएम) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पटाखों को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश दिए थे। जस्टिस एमएम सुंदरेश और



जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की। उसने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं होने से उसके आदेश सिर्फ सैद्धांतिक बनकर रह गए हैं। बार-बार नियमों का उल्लंघन होने से आदेशों का मजाक बन रहा है। पीठ ने अधिकारियों से कहा, आपने वास्तव में क्या किया? जब तक आप हमें यह नहीं बता सकते कि आपने क्या किया है, तब तक आदेश पारित करने का क्या मतलब है? फिर तो यह एक मजाक बन जाता है। पीठ ने ने कहा कि निर्देशों के पालन और उनके असर से जुड़े ठोस आंकड़े मौजूद नहीं हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या पिछले साल उसके आदेशों के बाद गठित निगरानी टीमों ने वास्तव में उन इलाकों का दौरा किया था, जिनकी पहचान की गई थी।



में एनवीएसआईसी की उपयोगिता भी मजबूत होगी। लेकिन यह लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है जब एनवीएसआईसी अपनी न्यूनतम आवश्यकता से भी कम क्षमता पर काम कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था = ऋद्ध्रकृष्ण-1ख का मिशन जीवन (10 साल) पूरा होने के

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 30 अक्टूबर को

रात 11.51 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से अपने जीएसएलवी-एफ 18 रॉकेट के जरिए अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-03 का प्रक्षेपण करेगा। जीएसएलवी-एफ 18 रॉकेट के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 20वीं उड़ान है। यह मिशन भारत के कमजोर पड़ते नाविक नेविगेशन तारामंडल को दोबारा मजबूत करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि वर्तमान में इसके पास स्वतंत्र रूप से सटीक पोजिशनिंग सेवाएं देने के लिए पर्याप्त सक्रिय उपग्रह मौजूद नहीं हैं। लगभग 50 मीटर ऊंचा और करीब 420 टन लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान (वजन) वाला यह रॉकेट, लगभग 2,250 किलोग्राम वजनी एनवीएस-03 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इस कक्षा की पृथ्वी से निकटतम दूरी 170 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 37,023

किलोमीटर और झुकाव 20.75 डिग्री होगा।

एनवीएस-03, इसरो की अगली पीढ़ी की नेविगेशन श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जिसे अब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन या एनवीएसआईसी कहा जाता है) की सेवाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनवीएसआईसी का उद्देश्य पूरे भारत और देश की सीमाओं से लगभग 1,500 चद्र आगे तक पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंगसेवाएं प्रदान करना है, जिससे विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता कम हो सके। इसरो ने बताया कि एनवीएस-03 में बाहर से ली गई घड़ियों के साथ-साथ एक स्वदेशी परमाणु घड़ी भी लगी है। इसमें मौजूदा क और स सिगनलों के अलावा स सिगनल को भी शामिल किया गया है। इससे और अधिक यूजर डिवाइस के साथ इसकी अनुकूलता बढ़ने की उम्मीद है, और साथ ही नागरिक तथा रणनीतिक कार्यों

^[1] इससे और अधिक यूजर डिवाइस के साथ इसकी अनुकूलता बढ़ने की उम्मीद है, और साथ ही नागरिक तथा रणनीतिक कार्यों

एमसीबी में कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान, कवर्धा में कांग्रेस का बड़ा हमला

■ **डॉ. देवाशीष पटनायक ने उठाए मतदाता सूची में गड़बड़ी के सवाल. कवर्धा में कांग्रेस का बड़ा हमला,**

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। लोकतंत्र में मताधिकार की सुरक्षा और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठते हुए कांग्रेस ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत अपना जनजागरण तेज कर दिया है। इसी क्रम में एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के ऑब्जर्वर डॉ। देवाशीष पटनायक पहुंचे। यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उन्होंने आगामी 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित बड़े आंदोलन की घोषणा करते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास



महंत, प्रभारी सचिव जारिता लैतफलांग, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, जिला प्रभारी उत्तम वासुदेव सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची की शुद्धता पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉ। देवाशीष पटनायक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर

आवाज उठा रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विषय को जनता के सामने लाना और लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना है। इसी कड़ी में कांग्रेस देशभर के जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से अपनी बात रख रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर

असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों का उचित समाधान किया जाना चाहिए। पटनायक ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल के रूप में उठा रही है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मतदाता पहचान संबंधी विवरणों की जांच करें और किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराएं। पत्रकार वार्ता के दौरान जब मतदाता सूची से नाम काटे जाने और चुनावी परिणामों पर उसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल किए गए तो पटनायक ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।

नाजिया इलाही खान, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक याचिका दायर



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नाजिया इलाही खान के खिलाफ याचिका दायर की गई है। नाजिया इलाही खान के विरुद्ध झहखुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता डॉ। आमिर खान और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ। सितारा खान के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दायर की गई है।

26 अक्टूबर 2026 को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए नाजिया इलाही खान को नोटिस जारी किया तथा राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता पक्ष अधिवक्ता डॉ। आमिर खान और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ। सितारा खान के अनुसार, %नाजिया इलाही खान की ओर से अपने विभिन्न भाषणों

में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट से बातचीत के दौरान उनपर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों में नाजजगी है।%याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसी क्रम में अधिवक्ता डॉ। आमिर खान के माध्यम से संबंधित झड़ूक एवं अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी आपराधिक याचिका दायर की गई है, जिसमें संबंधित प्रकरण में कानूनी कार्रवाई तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

करण राठौर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ के बहुचर्चित करण राठौर हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने प्रकरण में सात आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बलवा के अपराध में सभी सात दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्धदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं, प्रकरण में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि को बीएनएस की धारा 249 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

5 सितंबर 2025 की रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ के बतारा लाइन स्थित हनुमान मंदिर के सामने वाली गली में घटना हुई थी। घटना के समय करण अपने दोस्त रोहित चंदेल के साथ स्टेशन रोड पर था। तीन परिचित युवकों में से दो युवक करण को एक गली में ले गए, जहां विवाद के दौरान उसपर चाकू से हमला कर दिया। लहलुहान हालत में करण को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर



7 आरोपियों को आजीवन कारावास

दिया।घटना के बाद मामला गंभीर आपराधिक प्रकरण के रूप में सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 नाबालिग थे। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। ट्रायल के बाद कोर्ट ने सात आरोपियों को हत्या और बलवा से संबंधित अपराधों में दोषसिद्ध पाया। दोषसिद्ध आरोपियों में रितिक मिश्रा, सचिन जैन, राशिद खान, अमन कंठट उर्फ बुटई, भावेश

पाटिल, रौनिल मिश्रा उर्फ कुक्कू और मोहम्मद अकरम उर्फ अक्कू शामिल हैं। न्यायालय ने सातों दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (ड्रफ्ट) की धारा 191(3) के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्धदंड से दंडित किया है। वहीं, धारा 103(1) सहपठित धारा 191 के तहत हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक दोषी पर 1,000 रुपये का अर्धदंड लगाया है। कोर्ट ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अर्धदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आदेशानुसार अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि के विरुद्ध

छात्रावास अधीक्षकों की बस्तर में हड़ताल

5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी



करने में असमर्थ है। जिनमें अवकाश, दायित्व और कार्य अवधि शामिल हैं। 24 घण्टे छात्रावास में मौजूद होने से उनका निजी जीवन समाप्त हो रहा है। वहीं पदोन्नति की भी बड़ी समस्या है। छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्त होकर रिटायर्ड भी उसी पद में हो रहे हैं। जबकि अन्य विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया है। यदि सरकार हमारी मांगों पूरी नहीं करती है, तो आगामी 12 नवंबर को एक दिवसीय और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जिला सचिव रामेश्वरी साहू ने कहा, कार्य के दौरान महिला अधीक्षकों को काफी

दिक्रतों का सामना करना पड़ता है। महिला अधीक्षकों को छात्रावास में निवास करना पड़ता है। जिसमें उनके परिवार की अनुमति नहीं होती है। जिसके चलते बेटा, पिता और पति के प्रति दायित्व छूट जाता है। काम के कारण अपनी निजी जीवन को संतुलित करने में परेशानी होती है। इसीलिए हमारी यह मांग है कि अधीक्षकों का आवास परिसर में हो, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा रहे और प्रवेश द्वार पृथक हो। ताकि परिवार और अधीक्षक के दायित्वों का निर्वहन किया जा सके।

आशाराम की फोटो वाली पुस्तक बांटने पर एक्शन

■ **स्कूल शिक्षा विभाग के जिला मिशन समन्वयक को डीपीआई ने सस्पेंड करने का आदेश जारी किया.**



अधिकारियों से सामने दर्ज कराई। जिसके बाद प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ डीईओ ने कार्रवाई करते प्रभारी प्राचार्य को पद से हटा दिया गया है। हटाए गए प्राचार्य की जगह व्याख्याता कुलेश्वर सिंह को प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में डीएमसी यानी कि जिला मिशन समन्वयक के पद पर कार्यरत चंद्रभूषण गुप्ता को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश के मुताबिक डीएमसी चंद्रभूषण गुप्ता जिनका मूल पद व्याख्याता है, जो डीएमसी के प्रभार पर इस पद पर थे उनके द्वारा छात्रावास अधीक्षिका को बिना नोटिस उनके पद से स्थानांतरण के द्वारा तत्काल शिक्षिका को अधीक्षिका का प्रभार सौंपते हुए अटैच कर दिया था। इसकी शिकायत लोक शिक्षण संचालनालय में किया गया।

दरअसल, बीते दिनों बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल के बच्चों को, जेल में सजा काट रहे आशाराम बापू की फोटो लगी पुस्तक बांटने के मामले में बच्चों के परिजनों ने नाजजगी जाहिर की थी। इस बात की परिजनों ने शिकायत भी संबंधित

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

कबीरधाम में धान खरीदी से पहले बड़ी कार्रवाई

कबीरधाम। 15 नवंबर धान खरीदी सीजन से पहले कबीरधाम जिला प्रशासन ने अवैध धान कारोबार और बिचौलियों की गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य विभाग और मंडी समिति की संयुक्त टीम ने जिले के पांच स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 216 बोरी धान जब्त किया। जब्त धान का कुल वजन 86.40 क्विंटल है। मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान बजरंगबली ट्रेडर्स, उड्डियाकला (सहसपुर लोहारा) से 60 बोरी धान जब्त किया। भाोजम पटेल, बिडोरा के यहां से 40 बोरी पेखन साहू, कल्याणपुर से 55 बोरी परमात्मा ट्रेडर्स, भागुटोला से 50 बोरी और अजय नाग, तरेगांव जंजल से 11 बोरी यानी 4.40 क्विंटल धान बरामद किया गया। प्रशासन को इस कार्रवाई से अवैध रूप से धान का भंडारण करने वालों में हड़कंप मचा है। जिला प्रशासन का कहना है कि आगामी धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बिचौलियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सोलर प्लेट और पंप चोरों की ग्रामीणों ने की पिटाई

सूरजपुर। चेंद्रा चौकी क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गए तीन युवकों और एक नाबालिग को ग्रामीणों ने ना सिर्फ घेरकर पकड़ा बल्कि उनकी धुनाई भी की। मामला सूरजपुर पुलिस तक पहुंचा और चेंद्रा पुलिस चौकी प्रभारी ने चोरों को भीड़ से छुटाया और चौकी लेकर पहुंचे। सूरजपुर एसडीओपी अधिषेक पैकरा ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चेंद्रा चौकी क्षेत्र के बेनेडांड में रात में अज्ञात चोर सोलर प्लेट और 5 एचपी का पंप चोरी कर पिकअप में सवार होकर भाग रहे थे।ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। ग्रामीणों ने पिकअप को घेरा लेकिन आरोपी चोर वहां से निकलकर भाग गए थे। लेकिन ग्रामीण शांत नहीं बैठे। दूसरे दिन सुबह ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। चार आरोपियों में एक स्थानीय निवासी, दो अन्य और एक नाबालिग भी शामिल था। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उनको पीटने लगे। लेकिन इसी दौरान चेंद्रा चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और भीड़ से आरोपियों को छुटाया और उन्हें अपने कब्जे में लेकर चौकी पहुंचे।

नशीली टैबलेट के साथ 3 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा

बालोद। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से नीट्रोसन –10 की 1,500 टैबलेट बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी इन गोलियों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस के अनुसार, जिले में नशीले पदार्थों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एसपी किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। 27 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि तांदुला नदी किनारे रामघाट मंदिर के पास कुछ लोग बाइक और स्कूटी में नशीली दवाइयां लेकर ग्राहक तलाश रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश् दी। इस दौरान तीन संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान नवीन चावला, आशीष निर्मलकर और किशन बहादुर उर्फ नेपाली के रूप में की है।

25 हजार रुपए रिश्तत लेने के मामले में पटवारी निलंबित

बिलासपुर। शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपये की रिश्तत लेने के मामले में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी पूर्व में पटवारी हल्का नंबर 14 में पदस्थ थे और वर्तमान में तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत थे। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। आदेश में पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए शासन की छवि भूमित करने वाला बताया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

कॉलेज प्रोफेसर की शर्मनाक करतूत, किया गिरफ्तार

कांकर। जिले में छात्रा को टेलीग्राम के जरिए अश्लील वीडियो भेजने और प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देकर परेशान करने के आरोप में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान पीयूषकांत नेताम के रूप में हुई है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने 27 अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर पीयूषकांत नेताम ने 25 सितंबर 2026 को टेलीग्राम के जरिए उसे अश्लील वीडियो भेजा था। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रोफेसर पहले भी उससे अश्लील बातें करता था। शिकायत के अनुसार, आरोपी पर प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देकर छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप है।

कत्लखाने में मिला 9 क्विंटल गौमांस : 27 गायों का किया गया रेस्क्यू

जगदलपुर। बस्तर जिले के गौ सेवकों द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच ओडिशा के कोटपाड़ में 27 गायों को कत्लखाने से बचाया गया। वहीं मौके से लगभग 9 क्विंटल गौमांस भी बरामद किया गया। गौ सेवकों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जिले के गौ सेवकों ने ओडिशा के विधायक रूपु भतरा से मुलाकात कर गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण का विषय प्रमुखता से उठाया थाद्य इसके बाद कोटपाड़ में यह कार्रवाई हुईद्य पुलिस कार्रवाई के बाद कत्लखाने से बचाई गई 27 गायों में से 19 गायों को जिले के कुर्दी स्थित हैप्पी कामधेनु गौशाला को सुपुर्द किया गया, जबकि 8 गायों को कोटपाड़ के स्थानीय गौपालकों को सौंप दिया गया। गौ सेवकों के अनुसार, इस मामले का एक



गंभीर पहलू गौमांस के कारोबार का संभावित विस्तार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक होना है। उनका कहना है कि पूर्व में पकड़े गए एक गौमांस तस्करी के आरोपी ने स्वीकार किया था कि वह कोटपाड़ क्षेत्र से गौमांस का परिवहन कर बेचता है। ऐसे में गौ सेवकों ने संबंधित एजेंसियों से मामले की व्यापक जांच कर गौवंश वध, गौमांस के परिवहन और बिक्री से जुड़े

सुरक्षा के लिए इस पूरे मामले से जुड़े लोगों, परिवहन के रास्तों और मांस की बिक्री के संभावित ठिकानों की भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। गौ सेवक रोहन घोष ने कहा कि ओडिसा में भाजपा की सरकार बनने के बाद कोटपाड़ में 27 गायों को बचाया जाना सराहनीय है

द्य उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों को मामले की तह तक जाकर यह पता लगाना चाहिए कि गौमांस का स्रोत क्या था, उसका परिवहन किन रास्तों से किया जा रहा था। यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर और ओडिशा के गौ सेवक आपसी समन्वय के साथ गौवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गौ सेवा आयोग के सदस्य दीपक पनपलिया ने कोटपाड़ में गौवंश को बचाने और गौमांस बरामदगी की बड़ी कार्रवाई के लिए ओडिशा के विधायक रूपु भतरा के साथ पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया द्य उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले की गहन जांच कर गौवंश वध एवं गौमांस के अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रिहायशी इलाके में पहुंचा एल्बिनो भालू

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।

पेण्ड्रा-बिलासपुर मुख्य मार्ग पर पटियाला हाउस के पास बुधवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक दुर्लभ सफेद भालू जंगल से भटककर सीधे रिहायशी इलाके और मुख्य सड़क पर आ पहुंचा। मुख्य मार्ग पर भालू की चहलकदमी देख आवागमन कर रहे राहगीर थम गए। इस दौरान उन्होंने मोबाइल में भालू का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वन विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई अलग प्रजाति का भालू नहीं है, बल्कि भारतीय काले भालू (स्लोथ बिबर) का ही रूप है। अनुवांशिक विचार यानी



‘एल्बिनिज्म’ (रंग वर्ण दोष) के कारण इसका रंग काला न होकर पूरी तरह सफेद होता है। बता दें कि इससे पहले भी मरवाही वनमंडल के जंगलों में इस सफेद भालू की मौजूदगी देखी जा चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई और तत्काल मौके पर पहुंचकर भालू की निगरानी शुरू कर दी।

किसी भी संभावित मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विभाग भालू को सुरक्षित रूप से वापस घने जंगल की ओर मोड़ने के प्रयास में जुटा हुआ है। वन अधिकारियों ने राहगीरों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे भालू के पास न जाएं, न ही उसे घेरने या उकसाने की कोशिश करें।

संक्षिप्त समाचार

शाह ने चक्रवात अर्नब के महेनजर प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की

नई दिल्ली/रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चक्रवात अर्नब के महेनजर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की है। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चक्रवात अर्नब×स3 के महेनजर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने इन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को इस आपदा के समय लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रियता के साथ युद्धस्तर पर बचाव व राहत कार्य कर रही हैं। आपदा के प्रभाव का आंकलन करने और आगे की आवश्यक सहायता तय करने के लिए जल्द ही आईएमसीटी (अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें) भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के साथ खड़ी है।

मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर 12 पर्यवेक्षकों की परीवीक्षा अवधि समाप्त

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 पर्यवेक्षकों की विभागीय परीवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। विभागीय समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर 22 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ। परीवीक्षा अवधि पूरी करने वाले पर्यवेक्षक बस्तर, कोडगांव, दूतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें श्रीमती माया यादव, सुश्री अनुका चन्द्रवंशी, सुश्री धनेश्वरी नाग, श्रीमती रितु देवांगन, सुश्री रजनी भीमना, श्रीमती संध्या साहू, श्रीमती डिम्पल साहू, श्रीमती तुषि शर्मा, श्रीमती अंजू सिंह, सुश्री अम्बा पटेल, सुश्री गुंजा ध्रुव और श्रीमती कंचन माहेश्वरी शामिल हैं। श्रीमती तुषि शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के आधार पर परीवीक्षा अवधि समाप्त करने की कार्यवाही की गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उन्हें स्थायी किया जाएगा।

खमतराई मुक्तिधाम में नागरिकों की सुविधा हेतु लगाई गई कुर्सियां

रायपुर। नगर निगम जोन 1 द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत वीर शिवाजी वार्ड अंतर्गत खमतराई मुक्तिधाम परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वच्छता कायम की एवं मुक्तिधाम परिसर में नागरिकों की सुविधा हेतु कुर्सियां लगाने की व्यवस्था गयी। वहीं पुरे मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता कायम करते हुए खमतराई मुक्तिधाम की दीवाल पर पेंटिंग एवं रंगरोगन कराकर उसे सीटीयू स्वच्छता लक्षित ईकाई के अंतर्गत सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया। इसी प्रकार नगर निगम जोन 3 द्वारा जोन 3 अंतर्गत गुरू गोविंद सिंह वार्ड कर्मांक 29 अंतर्गत गोविंद नगर में सीटीयू स्वच्छता लक्षित ईकाई का विकास वहां नागरिकों द्वारा कचरा डाले जाने से बन गये मुक़्कड़ की सघन सफाई करवाकर एवं मुक़्कड़ के स्थान पर सीटीयू के अंतर्गत सौंदर्यीकरण कार्य उक्त स्थल में करते हुए वहां स्वच्छता जनजागरण स्लोगन लिखवाकर एवं नागरिकों हेतु कुर्सियों की व्यवस्था कर पर्यावरण संरक्षण हेतु गमले रखवाकर उस उक्त स्थल को सुन्दर स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया गया।

कानफोड़ डीजे के खिलाफ लामबंद हुआ मेडिकल जगत, दर्ज कराई आपतियाँ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित कोलाहल नियंत्रण अधिनियम विधेयक, 2026 के प्राारूप पर आपतियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले रायपुर के मेडिकल जगत ने एकजुट होकर पहल की है। शहर के प्रमुख चिकित्सकों, मेडिकल कॉलेज एवं एम्स के डॉक्टरों, पीजी रोजिडेंट्स, मेडिकल एवं आयुर्वेदिक छात्रों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तथा जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस को अपनी आपतियाँ एवं सुझाव प्रेषित किए हैं।

तकनीक आपको सक्षम डॉक्टर बनाएगी, लेकिन संवेदनशीलता आपको बेहतर डॉक्टर बनाएगी : मुख्य सचिव विकासशील

रायपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में वार्षिक उत्सव इम्पेटस-2026 का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की 63 वर्षों की उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को समर्पित इस उत्सव में विद्यार्थियों ने विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं सांख्यिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्सव के अंतर्गत गीत-संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम यूरोपरिया-2026 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने संगीत की विभिन्न विधाओं में मनमोहक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बुधवार शाम महाविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के



मुख्य सचिव विकासशील ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री तिरेश प्रवाल तथा महाविद्यालय के अग्र्व डीन डॉ. चंद्र कुमार शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे।

चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी ने मुख्य अतिथि के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन 2025-2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में चिकित्सा

पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएँ स्काउट्स-गाइड्स : राज्यपाल

लोकभवन में 1122 स्काउट्स-गाइड्स को राज्यपाल ने प्रदान किए राज्य पुरस्कार, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्काउटर-गाइडर भी सम्मानित

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल और जंगल को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्काउट्स एवं गाइड्स पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी साबित हो रही हैं।

राज्यपाल श्री रमेन डेका आज लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर से चयनित 1122 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने की।

राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं



देते हुए कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स का आदर्श वाक्य ‘तैयार रहो’ हमें विषम परिस्थितियों का सामना करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करना गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सभी प्रतिभागी समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय योगदान दें और अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बनें।

राज्यपाल श्री डेका ने राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बस्तर क्षेत्र से आए स्काउट्स एवं गाइड्स की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के ख़ात्मे के बाद बस्तर में शांति स्थापित हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय को पहचानना और निरंतर संघर्ष करना आवश्यक है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही

लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नियम और प्रतिज्ञाएं इसके सदस्यों को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। स्काउटिंग की वर्दी अनुशासन, सेवा और समर्पण के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग से जुड़ा व्यक्ति जीवनभर सेवा के भाव के साथ कार्य करता है। राज्यपाल के हाथों प्राप्त सम्मान प्रतिभागियों के लिए अविस्मरणीय उपलब्धि है और उन्हें आगे भी समाजसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक स्काउट्स एवं गाइड्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं।

समारोह में प्रदेशभर से चयनित 405 स्काउट्स, 528 गाइड्स, 64 रोवर्स और 125 रेंजर्स को राज्यपाल श्री रमेन डेका के हाथों राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस अवसर पर स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्काउटर योगेश्वर प्रसाद गांगुली (बालोद), सर्वश्रेष्ठ गाइडर तनुजा बंजारे एवं लता वैष्णव (महासमुंद), सर्वश्रेष्ठ रोवर राजमणि बंजारे एवं चंद्रशेखर पंकज, सर्वश्रेष्ठ रेंजर कुमारी

बिभूति वर्मा एवं कुमारी कृति बिजौर, सर्वश्रेष्ठ स्काउट ईश साहू, हरीश कुमार खोटे एवं राजवीर भट्ट तथा सर्वश्रेष्ठ गाइड दिव्या पटेल एवं दीप्ति पटेल को सम्मानित किया गया।

स्काउटिंग के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवाओं के लिए शैलेंद्र मिश्रा, आनंद राम बघेल, पवन कुमार नायक, विनोद कुमार हथेल, शशि बंछोर और रजनी रेड्डी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान पीपिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। इसमें लोकभवन में पदस्थ एडीसी श्री उदित पुष्कर (आईपीएस) को रैंक बैज लगाकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. आर. प्रसन्ना, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंंदरजीत सिंह खालसा, राज्य सचिव अमित कुमार क्षत्रिय, कार्यक्रम प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) पूनम सिंह साहू, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) जलवती साहू, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) सरिता पांडे सहित संगठन के पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित थे।

केदार कश्यप, दीपक बैज सहित 116 नेताओं की सुरक्षा में बड़ी कटौती

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है। बस्तर संभाग के भाजपा और कांग्रेस से जुड़े 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। बताया जा रहा है कि कई नेताओं की सुरक्षा जेड+ से जेड, वाई+ को वाई और जेड को वाई श्रेणी में कर दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा और कांग्रेस के नौ नेताओं की सुरक्षा जेड+ श्रेणी से घटाकर जेड श्रेणी की गई है। इनमें छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गामड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कर्मा परिवार को मिल रही



सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है।

बस्तर क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती किए जाने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा श्रेणी में बदलाव का निर्णय नक्सलवाद के ख़ात्मे के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और नेताओं को मौजूदा सुरक्षा खतरे के आकलन के आधार पर की जा रही समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

दस कोटि नशा मुक्ति जन प्रतिज्ञा महाअभियान में रायपुर पहले स्थान पर

रायपुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा नाराकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के साथ प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप रायपुर संभाग से पन्द्रह लाख से अधिक लोगों को इस महाअभियान से जोड़कर रायपुर सेवाकेन्द्र पूरे देश में पहले स्थान पर रहा जिसके लिए संस्थान द्वारा माउण्ट आबू में वैश्विक शिखर सम्मेलन में रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी को सम्मानित भी किया गया।

उल्लेखनीय है कि ब्रह्माकुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा आयोजित इस देशव्यापी महाअभियान का वचुअल शुभारम्भ 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था। इसमें मेडिकल विंग द्वारा दस कोटि जन प्रतिज्ञा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से अब तक पूरे देश में कुल आठ कोटि जनप्रतिज्ञा हासिल की जा चुकी है। रायपुर सेवाकेन्द्र की इस उपलब्धि पर माउण्ट आबू में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में मेडिकल विंग के सचिव डॉ. बनारसी



शाह और जाने-माने कैंसर सर्जन डॉ. अशोक मेहता द्वारा रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार ग्रहण करते समय इन्दौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी भी उपस्थित थी। रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने नशामुक्ति जनप्रतिज्ञा महाअभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन सहित नगर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्धजनों का आभार माना है जिनके सहयोग से यह कार्य सम्भव हो सका।

छत्तीसगढ़ मंत्रालय में श्रीकांत, के.पी. और मंजूषा को मिली नई जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल के तहत श्रीकांत वर्मा, के.पी. दीवानगन और मंजूषा राजपूत को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव में उप सचिव श्रीकांत वर्मा को नया अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, अवर सचिव के.पी. दीवानगन की पदस्थापना गृह विभाग में की गई है। इसके अलावा मंजूषा राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

श्रीकांत वर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीकांत वर्मा वर्तमान में खनिज साधन



विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। नए आदेश के तहत उन्हें उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खनिज साधन विभाग में उनकी मौजूदा जिम्मेदारी पहले की तरह बनी रहेगी।

के.पी. दीवानगन की गृह विभाग में पदस्थापना

अवर सचिव के.पी. दीवानगन की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है।

वे अब तक सामान्य प्रशासन विभाग के पूल में पदस्थ थे। जारी आदेश के अनुसार, उन्हें गृह विभाग में पदस्थ किया गया है। हालाँकि, आदेश में गृह विभाग की किसी विशेष शाखा या उन्हें सौंपे जाने वाले अलग कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

मंजूषा राजपूत को खाद्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार

मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत मंजूषा राजपूत को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वे वर्तमान में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदस्थ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार उन्हें मौजूदा कर्तव्यों के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ खाद्य विभाग से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।

न्यायालय तहसीलदार गोबरा नवापरा जिला रायपुर छ.ग.
<div>सूचना पत्र /नोटिस</div>
<div>इस सूचना पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आवेदिका अलंकृति सेमुअल पिता डेनियल सेमुअल निवासी नूनी चौक राजतालाल रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम तर्त प.ह.नं. 02 रा.नि.म. तोरला तहसील गोबरा नवापरा जिला रायपुर छ.ग. स्थित खसरा नं. 73/1, 81, 75, 80/2, 328, 77, 382/1, 386, 392, 397, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384/3,384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/9 का नाम रकबा 1650 वर्गफुट (प्लॉट नं. 29) भूमि को अनावेदिक/विकेता श्री कलवल वर्मा पिता श्री भावती प्रसाद वर्मा के द्वारा आवेदिका/विकेता के पक्ष में पंजीकृत नैयामा दिनांक 28/03/2012 के माध्यम से निष्पादित किया गया। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि का पंजीकृत नैयामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत् आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तत्त्वबन्ध में प्रकरण इस न्यायालय में विचारार्थीन है। उक्त प्रकरण में आप वर्तमान भूमिसूच्यमी / विकेता है।</div>
<div>अतः सूचनाई दिनांक 16/11/2026 को आप सूचना अथवा अपने मान्यता प्राप्त अधिकारी अथवा अधिकवार के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।</div>
<div>आज दिनांक 26/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।</div>
<div><div></div><div>तहसीलदार</div></div>

नाम परिवर्तन सूचना
<div>मैं तुषार देवदास (पुराना नाम जिसे बदला जाना है) उम्र 23 वर्ष पिता-पुरुषोत्तम देवदास, पता-विश्वास प्रोविसन, विकास नगर, गुढ़ियारी, थाना व पोस्ट-गुढ़ियारी, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड-492001 ने अपना (पुराना नाम) तुषार देवदास TUSHAR DEV-DAS को बदलकर (नया नाम) ग्लामिका देवदास GLAMIKAA DEVDAS रख लिया है।</div>
<div><div></div><div>तुषार देवदास गुढ़ियारी, रायपुर</div></div>

FORM-I NOTICE TO BE PUBLISHED IN NEWSPAPER FORM I, Hriday Ram (Old Name, which is to be changed) Son of Bishat Ram sahu, Village/City Ward No.16, Matha Talab Para, Biroda, Post-Kolar, Tehsil-Abhanpur, District Raipur Chhattisgarh pin code-493661 have changed my name from Hriday Ram (Old name) to Hirde Ram Sahu (new name).
<div><div></div><div>Hriday Ram Biroda, Abhanpur</div></div>

FORM-I NOTICE TO BE PUBLISHED IN NEWSPAPER FORM I, Tulsi Bai Patel W/o Mahesh Patel mother of Omshikha Patel, Village/City House No. 109, Veer Savarakar Nagar, Sondongari Post-Tenduwa (492099), Tehsil and District Raipur Chhattisgarh, have changed my minor Daughter name from Onsika Patel (Old name) to Omshikha Patel (new name).
<div><div></div><div>Tulsi Bai Patel Sondogari, Raipur</div></div>

न्यायालय नायब तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. // ईशतहार //
<div>अ-6/वर्ष 2026-27 ग्राम- खण्डवा, प.ह.नं. 18, रा.नि.मं. केन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग.</div> <div>एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डामन सिंह पिता चुली लाल वर्मा निवासी चर्दीदा भिलई दुर्ग छ.ग. द्वारा ग्राम खण्डवा प.ह.न. 18 रा.नि.म. केन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि ख.नं. 301/4 रकबा 0. 040 हे. भूमि के राज्यस् अधिलेख में सगर वर्मा पिता डामन सिंह वर्मा के नाम दर्ज है। भूमिस्वामी सगर वर्मा पिता डामन सिंह वर्मा की मृत्यु दिनांक 02/02/2026 को हो गयी है। सगर वर्मा पिता सगर सिंह वर्मा अविवाहित अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि के राज्यस् अधिलेख में पत्नी नामांतरण के आधार पर पिता डामन सिंह वर्मा पिता चुली लाल वर्मा एवं माता श्रीमती अर्पिणा वर्मा पति डामन सिंह वर्मा का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।</div> <div>इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति वा संस्था को आपत्ति / खया प्रस्तुत करना हो तो वे नियत धरती तिथि दिनांक 12/11/2026 तक न्यायालय में पेश या अपने अधिभासक के माध्यम से लिखित में पेश कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।</div> <div>आज दिनांक 23/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्र से जारी किया या।</div> <div><div></div><div>नायब तहसीलदार अभनपुर</div></div>

99वीं बार फेल काँग्रेस के शहजादे

विश्वास कैलाश सारंग

काँग्रेस के 56 वर्षीय युवा शहजादे राहुल गांधी चुनावी हार का शतक पूरा करने की दहलीज पर खड़े हैं। वो ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारतीय राजनीति के इतिहास के पहले यशस्वी एवं सफल नेता होंगे, जिनके नेतृत्व में चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है, अब वे जल्द ही चुनावी मैदान में हार का शतक लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उनके इस ताबड़तोड़ चुनावी हारों के प्रदर्शन से दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी खतरे में है। हालांकि रोहित शर्मा ने क्रिकेट के मैदान में दोहरा शतक लगाकर देश का गौरव बढ़ाया था। वहीं राहुल गांधी चुनावी हार का शतक लगाकर गांधी परिवार का गौरव बढ़ाएंगे। न भूतो न भविष्यति- जो पहले कभी नहीं हुआ और न ही भविष्य में कभी होगा ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले राहुल गांधी देश व दुनिया के एकमात्र नेता होंगे। वैसे भी महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। उनके इस सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बजाय हार के बाद सफाई देने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। चुनाव कैसे हारना है ये कला राहुल गांधी से सीखनी चाहिए। नतीजे चाहे जैसे भी आएँ, शहजादे का आत्मविश्वास हमेशा प्रथम श्रेणी में रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने वाले विद्यार्थी भी अपनी कमियों का विश्लेषण करते हैं, अपनी तैयारी सुधारते हैं और फिर नए उस्ताह के साथ परीक्षा के मैदान में उतरते हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनाव में पराजय के बाद ईवीएम, निर्वाचन प्रक्रिया और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। इसी का परिणाम है कि राहुल गाँधी के 99वीं बार फेल होने के बावजूद उनके नेतृत्व में सवाल ना उठाकर हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी मीडिया पर तो कभी कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया जाता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही परिवार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। राहुल गांधी को परिवारवाद की वजह से कुर्सी विरासत में मिल तो गई लेकिन उसे बनाए रखने के लिए जनता का विश्वास नहीं मिला है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत उसका राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि जनता का विश्वास होता है। परिवारवाद किसी व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश का अवसर दे सकती है, लेकिन जनादेश हासिल करने की गारंटी नहीं दे सकती है। राहुल गांधी को लगतार मिल रही असफलताओं से यह सिद्ध होता है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीति कोई पुरैतनी जागीर नहीं जिसमें परिवार का नाम ही योग्यता का प्रमाण-पत्र बन जाएगा। राहुल गांधी के लिए चुनाव मानो एक ऐसा आयोजन बन गया है, जिसमें उम्मीदों की फसल हर बार लहलहाती दिखाई जाती है, मगर नतीजों की कटई के समय कांग्रेस की राजनीतिक गोदाम खाली निकल आती है। इसके बावजूद राहुल गांधी के झूठे दावों की खेती बंद नहीं होती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं, हार के नतीजे आते हैं और फिर दावों की चमक फीकी पड़ जाती है। इसके बाद आरोपों की वर्ष पटकथा तैयार कर जनादेश का अपमान और वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता के बीच भ्रामक खबरे फैलाकर अपनी नाकामी छुपाई जाती है। राहुल गांधी की हालत उस विद्यार्थी जैसी होती जा रही है, जो हर साल परीक्षा में फेल होने के बाद नई कॉपी, नया पेन और नया बैग तो खरीद लेता है, लेकिन किताब खोलने की जहमत नहीं उड़ता है। फिर परिणाम आने पर कहता है कि परीक्षा का माहौल ठीक नहीं था।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

21. तथाकथित सौत्रान्तिक दर्शन सम्प्रदाय

गताक्त से आगे...

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि सौत्रान्तिक का मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त क्या था, इसीलिये सौत्रान्तिक सम्प्रदाय को भारतीय प्रमुख दर्शनों में स्थान नहीं दिया गया है। परन्तु कुछ लेखक दिङ्नाग सन्प्रदाय को ही सौत्रान्तिक मानते हैं।

उदाहरणार्थ डा0 सत्करी मुकुर्जी ने अपनी पुस्तक 'Universal Flux' में दिङ्नाग सम्प्रदाय को ही सौत्रान्तिक सम्प्रदाय माना है। श्वेतराकर ने दिङ्नाग सम्प्रदाय को सौत्रान्तिक या सौत्रान्तिक योगाचार लिखा है। वर्तमान लेखक ने ऋ.पने एक लेख 'The Sautrantika Theory of Knowledge' (देखो फुट-नोट p० 16) में यह दिखाया है कि दिङ्नाग सम्प्रदाय में शुद्ध प्रत्यक्ष केवल स्वलक्षण का होता है, परन्तु घट पट आदि दृश्यमान पदार्थों का जो कि सामान्यलक्षण पदार्थ माने गये हैं सविकल्पक ज्ञान माना जाता है। और व्यापक अर्थ में सविकल्पक ज्ञान



भी अनुमान के अन्तर्गत आ नाता है, इसलिये उस अर्थ में बाह्य पदार्थों को अनुमेय भी कहा जा सकता है यद्यपि यह अनुमेय होना उस प्रकार का नहीं है जैसा कि सर्वदर्शनसंग्रह में सौत्रान्तिक के मतानुसार दिखाया गया है जो कि लॉक के सिद्धान्त से मिलता है । इस प्रकार एक विशेष अर्थ में दिङ्नाग के सिद्धान्त में भी बाह्य अर्थ अनुमेय हो जाते हैं और कदाचित्त उस दृष्टि से दिङ्नाग सम्प्रदाय को सौत्रान्तिक माना गया हो। परन्तु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, (देखो परि0 6), दिङ्नाग सम्प्रदाय विषयवादी बौद्ध सम्प्रदाय माना जाता है, और उसका सौत्रान्तिक होना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं जैसा कि ऊपर कहा है सर्वदर्शन-संग्रह ने धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष के लक्षण को वैभाषिक के मत के अन्तर्गत देते हुये दिङ्नाग सम्प्रदाय को वैभाषिक माना है।

क्रमशः ...

ज्ञान/मीमांसा

सपा-कांग्रेस सीट में शेयरिंग या सफलता का खयाली पुलाव?

अजय बोकिल

चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान और कड़ई सौदेबाजी आम बात है। हर पार्टी चाहती है कि वह चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे ताकि चुनाव बाद सत्ता में आने पर वह ज्यादा हिस्सेदारी मांग सके। अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ा सके।

अमूमन सीट बंटवारे के लिए कोई न कोई सर्वमान्य फार्मूला तय किया जाता है। इसमें सम्बन्धित पार्टी का जनाधार, सीट जीतने की क्षमता, पिछले चुनावों में मिले वोट या फिर किसी ‘लेन देन’ की नीयत आदि मुख्य कारक हो सकते हैं। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी और कभी बरसों तक सत्ता में रही और अब हाशिए पर पहुंची कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जो खींचतान और सीट शेयरिंग के के दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, वह अपने आप में बेहद दिलचस्प और राजनीतिक सौदेबाजी का एक नया अध्याय है।

खास बात यह है कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में महज दो सीटें जीतने, चार पर नंबर दो रहने और 2.33 फीसदी वोट पाने वाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इस बार 180 सीटें तक मांग रही है। जबकि सपा अधिकतम 80 सीटें तक देने पर राजी बताई जाती है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सीटों का बंटवारा जीत की संभावना के हिसाब से तय होना चाहिए न कि आंकड़ेबाजी के आधार पर। जाहिर है कि सपा का लक्ष्य चुनाव जीतना है न कि सीटों को खैरात की तरह बांटना। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और राज्य में योगी सरकार के खिलाफ दस वर्षों की एंटी इकम्बेंसी के चलते वह इतनी मजबूत हो चुकी है कि आसन्न विधानसभा चुनाव में वह सपा के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकती है।

कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार राज्य में बढ़ा है। खासकर दलित और अल्पसंख्यकों में। यही कारण है कि कांग्रेस ने एक दलित नेता राजेन्द्र पाल गौतम को पार्टी का यूपी प्रभारी बनाया है और इमरान मसूद को राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर सपा अपना ही भला करेगी। हालांकि, राजनीतिक प्रेक्षक कांग्रेस के इस



अति आशावाद को पुरानी कहावत ‘ तोप का लायसेंस मांगोगे तो तमंचे का तो मिल ही जाएगा’ से जोड़कर देख रहे हैं। यानी 180 सीटें मांगेंगे तो 70-80 मिल ही जाएंगी। फिर चुनाव नतीजा जो हो। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। राज्य में विस चुनाव अगले साल मार्च में होने हैं।

यहां तार्किक सवाल यह है कि किसी भी चुनाव में सीटें मांगने या देने का बेस फार्मूला क्या हो? यानी विधानसभा चुनाव के लिए पिछला विस चुनाव परिणाम आधार माना जाए अथवा बीता लोकसभा चुनाव परिणाम बेस माना जाए? क्योंकि दोनो चुनावों की प्रकृति, मुद्दे और मतदाता की सोच अलग-अलग होती है।

हालांकि, कई बार जो नतीजा विस चुनाव में आया, लगभग वही कुछ समय बाद हुए लोकसभा में भी दिखा। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं होता। कभी-कभी वह उलटा भी हो सकता है, यह हम पहले देख चुके हैं। इसलिए सीट बंटवारे का व्यावहारिक फार्मूला पुराने आंकड़ों से ज्यादा वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के हिसाब सम्बन्धित पार्टी की हैसियत, जनाधार और जीतने की संभावना के आधार पर होना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।

जहां तक यूपी की बात है राज्य में इस बार पिछले विस चुनाव की तुलना में राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। 2022 के विस चुनाव में राज्य में नंबर दो की पार्टी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय समाज पार्टी (सुहेलदेव) से समझौता था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी 36.6 फीसदी वोट लेकर 111 सीटें जीती थी।

जबकि रालोद और सुहेलदेव भासपा का कुल वोट शेयर 1.73 फीसदी ही था। इसमें रालोद को 8 और सुहेलदेव पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि कांग्रेस अकेले 399

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने

होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्तूबर, 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता जहांगीर भाभा एक जाने-माने वकील थे। होमी भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा जॉन केनन स्कूल में हुई। भाभा शुरू से ही भौतिक विज्ञान और गणित में खास रुचि रखते थे। 12वीं की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से करने के बाद उन्होंने रॉयल इस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की परीक्षा पास की। साल 1927 में होमी भाभा आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। साल 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।

भारतीय परमाणु कार्यक्रम विश्व के

उन्नत और सफल परमाणु कार्यक्रमों में

शुमार किया जाता है। भारत

आज सैन्य और असैन्य परमाणु शक्ति-संपन्न राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। यह उस सपने का परिणाम है, जिसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ होमी जहांगीर भाभा ने संजोया था।

डॉ होमी जहांगीर भाभा यानी परमाणु भौतिकी विज्ञान का ऐसा चमकता सितारा, जिसका नाम सुनते ही हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। डॉ होमी जहांगीर भाभा ही वह शख्स थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की, और भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर हो के मार्ग प्रशस्त किया।

मुद्री पर वैज्ञानिकों की सहारता से परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू



करने वाले डॉ भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और अलग-अलग क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं की परिकल्पना कर ली थी। तब नाभिकीय ऊर्जा से मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि उन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।

भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के मिशन में प्रथम कदम के तौर पर उन्होंने मार्च, 1944 में सर दोग्रा जे. टाटा ट्रस्ट

को मूलभूत भौतिकी पर शोध के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। साल 1948 में डॉ भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1955 में संयुक्त

राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ‘शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग’ के पहले सम्मलेन में डॉ. होमी भाभा को सभापति बनाया गया।

होमी जहांगीर भाभा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के पक्षधर थे। 60 के दशक में विकसित देशों का तर्क था कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने से पहले विकासशील देशों को दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भाभा ने इसका खंडन किया। भाभा विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की वकालत करते थे।

वर्ष 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्रांवे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। वर्ष 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। यह होमी भाभा को देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि थी।

विपक्ष को चुनाव आयोग ने मिलकर दिया करारा जवाब!

नीरज कुमार दुवे

चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवालों की आड़ में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार हमला करना और तथ्यों के सामने आने के बाद भी राजनीतिक आरोपों की धार बनाए रखना लोकतांत्रिक विमर्श की स्वस्थ परंपरा नहीं हो सकती। हम आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे के जरिए उन आरोपों का जवाब दिया है, जिनके माध्यम से आयोग की निर्णय प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग का पक्ष सामने आने के बाद अब इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक आरोपों के चरम से दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। दस्तावेज क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है और अदालत के सामने कौन-सी दलीलें रखी गई हैं, यह देखना भी उतना ही जरूरी है।

हम आपको यह भी बता दें कि आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह को 10 दिन का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रींकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद करने का फैसला किया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होने की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि अदालत ने अभी न तो आयोग के पक्ष को अंतिम रूप से स्वीकार किया है और न ही याचिकाकर्ताओं के आरोपों को सही ठहराया है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मामले को आगे बढ़ाएगी।

दूसरी ओर, आयोग के हलफनामे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर से जुड़े तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025



और 14 मई 2026 को तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। आयोग के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से ही इन निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। हलफनामे को भी ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। साथ ही यहां एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। किसी फाइल पर किसी अधिकारी या निर्वाचन आयुक्त की टिप्पणी, सवाल अथवा सुझाव दर्ज होने का अर्थ अपने आप यह नहीं होता कि आयोग ने अंतिम निर्णय भी उसी टिप्पणी के आधार पर लिया। आयोग ने अपने हलफनामे में इसी अंतर को स्पष्ट किया है। उसका कहना है कि फाइलें निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक निर्वाचन आयुक्त से दूसरे निर्वाचन आयुक्त और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं। जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी भी ली जा सकती है, जिसे बाद में रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाता है। आयोग का तर्क है कि आंतरिक विचार-विमर्श को अंतिम निर्णय के साथ मिलाकर देखना उचित नहीं है।

यह दलील उन आरोपों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिनमें दावा किया गया था कि एसआईआर से जुड़े 14 निर्णय दोनों निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद आयोग के नाम पर लिए गए। लेकिन आयोग ने इन आरोपों के आधार को चुनौती देते हुए कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट अपने आप में आरोपों का निर्णायक कानूनी प्रामाण नहीं हो सकती। अब याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करना है और अदालत को यह तय करना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड से क्या निष्कर्ष निकलता है।

आज का इतिहास

1485 हेनरी टुडोर को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। हेनरी सप्तम के नाम से पहचाने गए हेनरी टुडोर ने टुडोर वंश की स्थापना की और इंग्लैंड की शक्ति के विस्तार के लिए कई तरह से प्रयास किए।

1611 गुस्टॉफ द्वितीय एडोल्फ 17 साल की उम्र में स्वीडन का राजा बना।

1909 भारत के भौतिक शास्त्री और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ।

1922 बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में सरकार बनाई।

1930 तुर्की तथा यूनान ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये।

1945 भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।

1956 भारत का पहला पांच सितारा होटल ‘अशोक’ खुला।

1960 ब्रिटेन में पहली बार सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट की गई।

1963 अफ्रीकी देश मॉरक्को तथा अल्जीरिया ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए।

1975 स्पेन में किंग जुआन कार्लोस ने सत्ता संभाली।

1980 मध्य अमेरिकी देशों हॉंडुरस तथा अल सल्वाडोर ने सीमा विवाद हल किया।

1994 बाल्कन देश मेसिडोनिया के संसदीय चुनाव में वामपंथी गठबंधन की जीत।

2001 लादेन के सम्पर्क में रहने के आरोपी 3 परमाणु वैज्ञानिकों को पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंपा।

2003 ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का भारत दौरा प्रारम्भ। अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने पाकिस्तान को भारत के साथ शांति वार्ता करने को कहा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतंत्र की बहाली के लिए अपनी कटिबद्धता घोषित की।

2004 उक्रेन ने फ्रांस को 3-1 से पराजित कर 39.5 अंक के साथ ओलंपियाड का स्वर्ण जीता।

2008 असम (भारत)की राजधानी गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर श्रेणिबद्ध धमाके हुए। इसमें 66 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

2008 स्टेट बैंक आफ पोंकानेर एवं जयपुर ने फिक्स डिपोजिट की व्याज दरों में एक प्रतिशत की कमी की।

2008 गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में कम से कम 18 धमाके हुए जिनमें 81 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई और 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

2013 तेलंगाना के महबूबनगर में बस में आग लगने से 44 लोगों की मौत।

त्योहारों के बीच सियासी टकराव: व्यापारी क्यों बन रहे हैं आंदोलन के मोहरे?

सौरभ वार्धोय

देश में त्योहारों का मौसम बाजारों में रौनक, कारोबार में तेजी और आम लोगों के चेहरों पर खुशियां लेकर आता है। दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान व्यापारी वर्ग पूरे साल की कमाई के एक बड़े हिस्से की उम्मीद करता है। दुकानदारों से लेकर छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और कर्मचारियों तक, लाखों लोगों की आजीविका इन दिनों के कारोबार पर निर्भर रहती है। ऐसे समय में यदि राजनीतिक आंदोलन, चुनावी रैलियां और विरोध-प्रदर्शन बाजारों तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने लगे, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता रहा है कि आखिर इस टकराव की कीमत व्यापारी वर्ग ही क्यों चुकाए ?

एक नवंबर को प्रस्तावित चुनावी रैली और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे राजनीतिक विरोध के बीच व्यापारिक संगठनों की ओर से त्योहारों के मद्देनजर उठाई जा रही मांगों ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को नई दिशा दे दी है। एक तरफ विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की जवाबदेही का सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग चाहता है कि त्योहारों के समय उसका कारोबार बाधित न हो। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन की रणनीति तय करते समय आम नागरिकों और व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए ?

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। सरकार से सवाल पूछना, चुनावी प्रक्रिया में परादर्शिता की मांग करना और संवैधानिक संस्थाओं

की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। यदि विपक्ष को चुनाव आयोग के कामकाज पर आपत्ति है, तो उसे तथ्य, दस्तावेज और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने या राजनीतिक संदेश देने से नहीं मापी जानी चाहिए। यह भी देखना आवश्यक है कि उस आंदोलन का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। त्योहारों के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही, माल की आपूर्ति, यातायात और दुकानों के संचालन में व्यवधान छोटे व्यापारियों के लिए गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

बड़े कारोबारी कुछ समय का नुकसान सहन कर सकते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार, दैनिक आय पर निर्भर विक्रेता और सीमित पूंजी से कारोबार करने वाले व्यापारी हर दिन की कमाई पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में व्यापारिक संगठनों की मांग को केवल राजनीतिक विरोध के चरम से देखना उचित नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि आंदोलन को लेकर राजनीतिक गतिरोध बढ़ रहा है, तो सरकार और संबंधित संस्थाओं को संवाद का रास्ता तलाशना चाहिए। हालांकि, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हैं कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा राजनीतिक पेच खड़ा किया है, जिससे आंदोलन समाप्त हो जाए या विपक्ष दबाव में आ जाए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी आरोप की विश्वसनीयता तथ्यों से तय होती है। सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष की



शिकायतों का जवाब दे, चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि के कारण आम नागरिकों के अधिकारों तथा आजीविका पर अनावश्यक असर न पड़े।

इसी तरह विपक्ष को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसका आंदोलन किन ठोस मांगों पर आधारित है, उसकी समय-सीमा क्या है और आम लोगों को कम से कम परेशानी पहुंचाते हुए उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग के शीर्ष पदाधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी मांग पूरी होने पर आंदोलन समाप्त हो सकता है, राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण विषय है। यदि विपक्ष का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, तो उसे अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग को भी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और परादर्शिता के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेकिन किसी संवैधानिक पदाधिकारी का इस्तीफा मांगना और उसे तत्काल स्वीकार कराना दो अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख का पद

किसी राजनीतिक दल की इच्छा से संचालित नहीं हो सकता। उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया कानून तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए यह कहना कि केवल इस्तीफा होते ही तीस सेकंड में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक वक्तव्य तो हो सकता है, लेकिन इसे समस्या के समाधान की गारंटी नहीं माना जा सकता।

यदि वास्तविक उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बहाल करना है, तो समाधान परादर्शी जांच, तथ्यों के सार्वजनिक स्पष्टीकरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन में तलाशना होगा। केवल इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना या बिना जवाब दिए मांग को खारिज कर देना, दोनों ही स्थितियां राजनीतिक गतिरोध को बढ़ा सकती हैं। व्यापारी किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। बाजारों में काम करने वाले लाखों लोगों के सामने किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन, माल की खरीद और बैंक की किस्तों जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। त्योहारों के समय बिज्री प्रभावित होने का नुकसान केवल दुकान के मालिक को नहीं, बल्कि उससे जुड़े पूरे परिवार और कर्मचारियों को भी उठाना पड़ता है।इसलिए व्यापारिक संगठनों की मांगों को गंभीरता से सुनना सरकार और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है। यदि रैली या आंदोलन के लिए स्थान, समय और मार्ग में बदलाव करके व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ऐसा करने में किसी पक्ष को राजनीतिक हार नहीं

माननी चाहिए।सरकार को कानून-व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का संतुलन बनाए रखना चाहिए। विपक्ष को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार इस्तेमाल करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी रणनीति से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। प्रशासन को भी निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए यातायात, सुरक्षा और बाजारों के संचालन के लिए स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल व्यापारियों को अपने पक्ष में खड़ा करने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करें। व्यापारिक संगठनों को भी अपनी मांगें स्पष्ट रूप से सामने रखनी चाहिए और राजनीतिक विवादों में किसी एक पक्ष का औजार बनने से बचना चाहिए। एक नवंबर की रैली और आंदोलन को लेकर यदि कोई विवाद है, तो संबंधित पक्षों के बीच तत्काल बातचीत होनी चाहिए। रैली के समय और स्थान का ऐसा निर्धारण किया जा सकता है, जिससे विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहे और त्योहारों का कारोबार भी प्रभावित न हो। इसके साथ ही चुनाव आयोग से जुड़े सवालों पर तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक संवाद होना चाहिए।

लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी विपक्ष का अधिकार भी है। विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जनता के हितों की रक्षा करना उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। इसी प्रकार सरकार को भी आलोचना को दबाने के बजाय उसका उत्तर देना चाहिए। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है कि राजनीतिक संघर्ष के बीच भी जनता के हित सर्वोपरि रहें।

इनके बयान ही काफी है इनके पतन के लिए



किया गया, तो ये किसी को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। अक्तूबर, 2024 में कर्नाटक की जनसभा में भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी करार दिया। नवंबर, 2022 में गुजरात में खड़गे ने हर चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ने को लेकर कहा था,

क्या पीएम के रावण की तरह 100 सिर हैं। खड़गे हो, राहुल गांधी या सोनिया गांधी हो कांग्रेस के उपरोक्त नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनके माता-पिता को लेकर एक बार नहीं अनेक बार अपभ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है। इन नेताओं की भाषा से प्रधानमंत्री मोदी को कोई राजनीतिक हानि तो नहीं हुई लेकिन खड़गे और गांधी परिवार की संकीर्ण सोच को अवश्य जगजाहिर कर दिया है

आपको पता है कि पिछले लम्बे समय से वोट चोरी के मामले पर जिस तरह बहुत बार आपे से बाहर होते रहे हैं दरअसल

इनमें दूषित मानसिकता पर किए हैं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा बहुत ओछी बयानबाजी की जाती रही है, वह कई बार मर्यादा से बाहर जाती दिखाई तो देती ही है परन्तु उससे उनके अंदर पैदा हो रही बौखलाहट का भी भली-भांति पता चल जाता है। पिछले 12 वर्ष से कांग्रेस को पार्टी के तौर पर बड़ी ऐसी राजनीतिक हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसकी उनकी उम्मीद नहीं थी, जिस कारण वह हर प्रयास अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जल्दबाजी में दिखाई देते हैं, परन्तु जिस तरह का व्यवहार बड़े कांग्रेसी नेताओं ने धारण कर लिया है, उससे उनकी कोई बड़ी प्राप्ति न होती दिखाई देने के साथ उनकी निराशा सिर चढ़ कर बोलती नज़र आ रही

आसान नहीं होगी लूला की राहः ब्राजील में धुर दक्षिणपंथ को झटका

गिल्मर्मे कासाराएस

तीन हफ्ते पहले तक ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के राजनीतिक भविष्य पर विराम लग चुका था। उनके राजनीतिक जीवन के अंत की घोषणाएं की जा चुकी थीं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दक्षिणपंथी फ्लेवियो बोलसोनारो, जो जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के बेटे हैं, पहले दौर के चुनाव में ऐसी बढ़त हासिल कर चुके थे, जिसे पाट पाना लगभग असंभव माना जा रहा था। 80 वर्ष की उम्र में लूला ब्राजील की राजनीति के केंद्र में चार दशक बिताने के बाद चुपचाप विदाई लेने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन, रविवार को लूला ने सभी को गलत साबित कर दिया।

उन्होंने दूसरे दौर का चुनाव जीतकर ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में अपना चौथा कार्यकाल हासिल कर लिया। यह ऐतिहासिक इसलिए है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई उम्मीदवार पहले दौर में जीत हासिल करने के बाद दूसरे दौर में हार गया हो। लूला ने तीन सप्ताह के भीतर पहले दौर में लगभग 22 लाख मतों से मिली हार को निर्णायक जीत में बदलकर इस परंपरा को तोड़ दिया। यही नहीं, अपना नया कार्यकाल समाप्त होने तक लूला कुल 16 वर्ष (नौ-लगातार) देश का शासन संभाल चुके होंगे। यह ब्राजील के इतिहास में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित किसी भी नेता का सबसे लंबा कार्यकाल होगा।

लूला की जीत का महत्व ब्राजील की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। इसके भी कुछ प्रमुख पहलू हैं। वैश्विक स्तर पर ब्राजील अब भी धुर दक्षिणपंथ के उभार के



खिलाफ एक मजबूत अवरोध बना हुआ है। लैटिन अमेरिका और यूरोप में हाल के चुनावों के दौरान लगभग हर जगह धुर दक्षिणपंथी दलों और नेताओं ने प्रगति की है। लेकिन, दुनिया के चौथे सबसे बड़े लोकतंत्र ब्राजील ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन आर्थिक प्रगति सीमित थी और उसका लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा था। तमाम संकेत लूला की हार की ओर इशारा कर रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को मात दे दी।

उनकी जीत उन नीति पर भी अंकुश लगाती है, जिसे आलोचक ‘डोनोर् सिंड्रोम’ कहते हैं। इसका आशय ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश से है, जिसके तहत शुल्क, धमकियों और राजनीतिक संरक्षण के जरिये पश्चिमी गोलार्ध को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में अधिकांश मजबूती से लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, लूला को अपनी राजनीतिक वापसी को अपनी नीतियों की पूर्ण स्वीकृति नहीं समझना चाहिए। यह सही है कि उन्होंने अपनी रणनीति में सुधार किया। तीन सप्ताह के भीतर उन्होंने सत्ता में अपने चार वर्षों के दौरान की गई गलतियों को स्वीकार किया, विशेष रूप से पहले दौर के कमजोर चुनाव अभियान के दौरान हुई चूकों को। उन्होंने अपना संदेश अधिक

स्पष्ट किया, गठबंधन का दायरा बढ़ाया और उन मतदाताओं से सीधे संवाद किया, जिनका समर्थन वह खो चुके थे। लेकिन, अब उन्हें ऐसे देश का शासन चलाना है, जो पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत हो चुका है। सड़कों पर राजनीतिक हिंसा बढ़ी है और इंटरनेट पर घृणास्पद भाषणों का प्रसार बेरोकटोक हो रहा है। धुर दक्षिणपंथ की प्रमुख हस्तियों, जिनमें निकोलस फरेरा और लूकास पावानातो शामिल हैं, ने पहले ही कह दिया है कि वे चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं करेंगे। रविवार देर रात बोल्योनारो ने भी कहा कि वह हार नहीं मानेंगे और मतदान को रद्द कराने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद अमेरिका का सवाल है। व्हाइट हाउस के बोल्लोनारो परिवार के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए इस बात का वास्तविक खतरा है कि ट्रंप प्रशासन चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए या उसे मान्यता देने से ही इन्कार कर दे।

जब लूला पांच जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तो तीन सवाल उनके चौथे कार्यकाल की दिशा तय करेंगे। पहला सवाल यह है कि वह गहरे विभाजन से जूझ रहे देश का शासन कैसे चलाएंगे, जहां संसद में रूढ़िवादी दलों का बहुमत है और एक दर्जन से अधिक राज्यों में दक्षिणपंथी गवर्नर हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान जिस विधायिका ने लूला को अपने दबाव में रखा, वह अब उनके प्रति और अधिक शत्रुतापूर्ण हो गई है। प्रत्येक बजट, हर सुधार और प्रत्येक नियुक्ति के लिए कठिन बातचीत करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लूला पर महाभियोग का खतरा भी मंडराता होगा।

दूसरा सवाल देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने का है। वह उन समस्याओं से

मनोज कुमार अग्रवाल

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. श्रीकृष्ण

सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित पटना में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एसआईआर से जुड़ा हर व्यक्ति जेल भेजा जाएगा। तभी एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा, जब तक कड़ा विद्रोह नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे। खड़गे ने शुरूआती शब्द नहीं सुने और केवल बाद वाला वाक्य सुनकर कहा, मोदी का बाप भी जाएगा। उन्होंने तीन बार यह वाक्य दोहराया। वहीं, सभागार में मौजूद अन्य कांग्रेसियों ने संबंधित कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी और बाहर निकाल दिया। खड़गे के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

देश के राजनीतिक मंच पर जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, वह चिंता पैदा करने वाला है। कई प्रकार की हो रही कार्रवाईयों के अलावा छोटे-बड़े नेताओं द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ कई बार इस तरह की बयानबाजी की जाने लगी है, जो मर्यादा की हद पार कर जाती है। लोकतंत्र में आपसी विचारधाराक विरोध नफरत और दुश्मनी में बदलता दिखाई दे तो वह पूरे प्रबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। निचले स्तर पर तो बहुत बार ऐसा कुछ दिखाई देता है परन्तु यदि यह ऊपरी स्तर तक पहुंच जाए और ऐसे दृश्य अक्सर देखने को मिलने लग जाएं तो यह पूरे राजनीतिक प्रबंध के लिए नुकसानदायक साबित नहीं होंगे, बल्कि समूचे ताने-बाने पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में देखा जाने लगेगा। इस संबंधी बड़े विवाद उस समय भी पैदा होता है, जब बड़े

अकेले ही संघर्ष करके लोकप्रिय होते योगी

हरीश गुप्ता

भाजपा में योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को शायद उम्मीद रही होगी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उनके पर करार दिए जाएंगे। टिकट वितरण में उन्हें पूरी छूट न देना मुख्यमंत्री पर लगाम कसने का एक तरीका माना जा रहा था। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है- क्या भाजपा उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा बन चुके नेता को हाशिये पर डालने का जोखिम उठा सकती है? योगी टिकट वितरण को लेकर सत्ता संघर्ष में उलझने से बचते नजर आ रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा के लिए हुए नामांकन के दौरान, आम धारणा के विपरीत, उन्होंने उन आठ सीटों के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की सूची लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने जाने का रास्ता नहीं अपनाया, जिन सीटों पर भाजपा की जीत की उम्मीद थी। इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि वह जिसे उपयुक्त समझें, उसे उम्मीदवार बनाएं। व्यापक रणनीति नए चेहरों को मैदान में उतारने की थी। बाद में, समझाने-बुझाने के बाद ही योगी ने कुछ नाम सुझाए। यह घटनाक्रम उनकी राजनीतिक शैली की एक झलक देता है। पार्टी के भीतर उनकी स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। 2017 में एक स्वतंत्र नेता के रूप में उभरने के बाद से योगी को केंद्रीय नेतृत्व, राज्य संगठन और आरएसएस के परस्पर विरोधी दबावों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ा है। संघ द्वारा उन्हें दिए गए समर्थन के अपने पहलू हैं, लेकिन भाजपा के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है। योगी की लोकप्रियता उनके कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख, कट्टर हिंदुत्ववादी रवैये और समर्थकों के बीच उनकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा के मेल पर टिकी है। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह संगठनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के साथ-साथ योगी द्वारा अर्जित राजनीतिक प्रभाव का भी सम्मान करे। इसलिए

टिकटों की यह लड़ाई महज इस बात तक सीमित नहीं है कि उम्मीदवारों का चयन कौन करेगा। इसके पीछे एक बड़ा सवाल है-उत्तरप्रदेश में भाजपा अपने इकलौते योद्धा नेता योगी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस किए बिना उन्हें कितनी छूट दे सकती है ?

भाजपा हाईकमान का डैमेज कंट्रोल-उत्तराखंड में दलेर मेहंदी और दिल्ली में दिलजीत दोसांझ से जुड़े विवादों के राजनीतिक नुकसान में बदलने की आशंका के बाद भाजपा हाईकमान नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। पंजाब और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकप्रिय पंजाबी सांस्कृतिक हस्तियों के साथ लंबे समय तक टकराव भाजपा को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका मिल सकता है कि भाजपा पंजाबी और सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी कर रही है। पार्टी नेतृत्व स्थानीय विवादों को बड़े राजनीतिक मुद्दों में बदलने से रोकना चाहता है। उत्तराखंड में विवाद तब शुरू हुआ, जब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कथित तौर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दलेर मेहंदी पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनका अपमान किया। उनके भाई मीका सिंह ने इस आरोप का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि दलेर शराब नहीं पीते और बड़ी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अनुपम खेर, कपिल शर्मा और बादशह सहित कई चर्चित हस्तियों ने मंत्री के व्यवहार की आलोचना की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दलेर मेहंदी से उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की और इस घटना पर खेद जताया। इससे विवाद के कारण पैदा हुई नाराजगी को कम करने में मदद मिली। दिल्ली में एक अलग विवाद तब सामने आया, जब नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम का पहले मंजूरी मिलने के बावजूद सुरक्षा कार्रवां का हवाला देकर कथित तौर पर अंतिम समय में अनुमति वापस ले ली गई।

प्रोड्यूसर बनने के बाद कहानी को देखने का बदला नजरिया



एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी इन दिनों अपनी फिल्म ‘मुझे जान ना कहो मेरी जान’ को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मार्केट तक ले जा रही हैं। इस साल की शुरुआत में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सफर शुरू करने वाली उनकी बतौर प्रोड्यूसर पहली फीचर फिल्म अब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) 2026 तक पहुंच गई है।

श्वेता का कहना है कि प्रोड्यूसर बनने के बाद कहानी को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। अब वह सिर्फ फिल्म बनाने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह भी सोचती है कि फिल्म किन लोगों तक पहुंचेगी और इसके जरिए किस तरह की बातचीत शुरू हो सकती है। श्वेता ने कहा, ‘‘आप जिस फिल्म पर भरोसा करते हैं, उसे किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाना अपने आप में खास होता है। खासकर तब, जब बतौर प्रोड्यूसर यह आपकी पहली फीचर फिल्म हो। बर्लिन से टोरंटो तक का सफर मेरे लिए बेहद खास रहा है, क्योंकि इस दौरान मुझे ‘मुझे जान ना कहो मेरी जान’ को एक अलग तरीके से पेश करने का मौका मिला।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘जब आप फिल्म को बनाने की प्रक्रिया से

आगे बढ़कर देखते हैं, तो आपके मन में यह सवाल आने लगते हैं कि फिल्म किन लोगों तक पहुंचेगी, इसके जरिए किस तरह की बातचीत शुरू हो सकती है और आगे इसके लिए क्या-क्या संभावनाएं हैं। यह मेरे लिए सीखने का शानदार अनुभव रहा है और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि इस सफर का फिल्म के लिए क्या मतलब निकलता है।’’ श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि बतौर प्रोड्यूसर काम करने से उन्हें कहानी कहने के तरीके को एक नए नजरिए से समझने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रोड्यूसर बनने के बाद कहानी कहने को लेकर मेरा नजरिया बदल गया है। एक एक्टर के तौर पर आप किसी किरदार और कहानी को पर्दे पर जीवत करने में पूरी तरह जुटे रहते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रोड्यूसर के तौर पर आपको यह भी देखना होता है कि फिल्म बनने के बाद उसका सफर कैसा होगा, कौन लोग इससे जुड़ सकते हैं और आप फिल्म को उसके दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किस तरह मौकें बना सकते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मार्केट ऐसे लोगों को एक साथ लाते हैं, जो इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने में मदद कर सकते हैं। अपनी पहली प्रोडक्शन को इन प्लेटफॉर्म पर पेश कर पाना मेरे लिए एक अहम कदम रहा है।’’

नेशनल अवॉर्ड जीत चुके फिल्ममेकर संजय नाग के निर्देशन में बनी ‘मुझे जान ना कहो मेरी जान’ में तिलोत्तमा शोम

और श्वेता त्रिपाठी नजर आएंगी। यह एक क्वीर लव स्टोरी है, जिसमें प्यार और इंसानी रिश्तों को ईमानदारी और बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। बतौर प्रोड्यूसर श्वेता का सफर थिएटर से शुरू हुआ था। साल 2010 में उन्होंने अपनी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी ‘ऑलमाइटी’ की शुरुआत की थी। इसकी पहली प्रस्तुतियों में ब्रिटिश नाटककार माइक बार्टलेट का क्वीर ड्रामा ‘कॉक’ शामिल था। माइक बार्टलेट ओलिवियर अवॉर्ड जीत चुके हैं।



एकता कपूर ने की प्रियंका चाहर चौधरी की तारीफ

अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में प्रोड्यूसर एकता कपूर द्वारा उनके गेम की तारीफ किए जाने के बाद इमोशनल नजर आईं। दरअसल, शो के टावर के अंदर साथी कंटेस्टेंट्स के साथ झगड़े के बाद माहौल गरम होने के बीच, प्रियंका को एकता, अभिषेक मल्हान और ईशा सिंह की तरफ से सपोर्ट मैसेज मिले। प्रियंका की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए एकता ने कहा कि वह शो में उनकी जगह देती हैं और उन्होंने जिस तरह से अलग-अलग हालात को हैंडल किया है, वह वाकई सराहनीय है।

एकता ने कहा, ‘मैं आपको ‘राइज एंड फॉल’ में देख रही हूँ और मैं कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा खेल रही हो। शो में आप कभी-कभी शांत और संयमित रहती हो और कभी-कभी लोगों को उनकी असली जगह दिखा देती हो।’ प्रियंका को ‘असली हीरोइन’ बताते हुए प्रोड्यूसर ने कहा कि वह पूरे देश में मौजूद उनके सपोर्टर्स के साथ उनके लिए दुआ कर रही हैं। एकता ने प्रियंका के साथ जुड़े ‘नागिन’ टैग पर भी बात की और इसे हौसला बढ़ाने वाला मैसेज बताया।

उन्होंने कहा, ‘सबसे अच्छी बात, अगर कोई आपको नागिन कहे, तो उन्हें ये बात याद हो कि नागिन का डसा पानी भी नहीं मांगता और आप सिर्फ बुरे लोगों को डसती हो। तो, खेलती रहो और जीतो। मेरे और पूरे इंडिया के लिए, आप असली हीरोइन हो, लोगों के दिल की, बालाजी की, मेरी और इंडियन टेलीविजन की। जीतो, क्योंकि मुझे नहीं पता, या आपको नहीं पता कि हारना



कैसे है।’ अभिषेक मल्हान और ईशा सिंह ने भी प्रियंका को अपना सपोर्ट दिया, जिसके बाद टावर के अंदर चल रही राइवेलरी के बीच हौसला बढ़ाने वाले शब्द सुनकर प्रियंका चौधरी इमोशनल हो गईं। बनिजय पशिया द्वारा प्रोड्यूस ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 के होस्ट पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं। यह शो प्राइम वीडियो पर फ्री में एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसके नए एपिसोड रोज दोपहर 12 बजे रिलीज होते हैं।

साई पल्लवी ने ‘रावण’ की भूमिका निभाने के यश के फैसले की तारीफ की

निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मेकर्स और फिल्म की कास्ट भारत के अलग-अलग शहरों में जाकर जोर-शोर से इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद में हुए एक इवेंट में फिल्म में ‘सीता’ का किरदार निभा रही साई पल्लवी ने फिल्म में ‘रावण’ की भूमिका निभाने के यश के फैसले की तारीफ की।

साई पल्लवी ने कहा कि यश ने इस किरदार को पूरी तरह अपना लिया और लोगों की नफरत के बजाय उनका प्यार हासिल किया। साई पल्लवी ने कहा, ‘कोई भी रावण का किरदार नहीं निभाना चाहता, क्योंकि इस किरदार के साथ नफरत जुड़ी होती है, लेकिन यश ने यह किरदार निभाया और इसके बदले सभी का प्यार जीता।’

क्यों यश ने निभाया ‘रावण’ का किरदार

इससे पहले एक बातचीत में यश ने बताया था कि फिल्म के सह-निर्माताओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने भगवान राम के बजाय रावण का किरदार निभाने का फैसला क्यों किया। यश ने कहा था, ‘राम की भलाई दिखाने के लिए रावण की बुराई भी तो चाहिए।’ अपनी एक्टिंग पर भरोसा जताते हुए यश ने कहा, ‘मुझसे अच्छी बुराई कोई दिखा नहीं सकता।’ फिर जब अभिनेता से पूछा गया कि तो क्या आपने पर्दे पर बुरा आदमी बनने की जिम्मेदारी ले ली है? इसके जवाब में यश ने कहा, ‘जब मैं अच्छा किरदार भी करूंगा ना, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं होगा।’ यश ने आगे कहा, ‘रावण को देखकर लगना चाहिए कि इसको कैसे मारा जाए? हम सभी ने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया है। रामायण में बात मेरे स्टारडम या एक स्टार के तौर पर मेरी पहचान की नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर सबसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं।’



क्या अक्षय कुमार के बेटे आरव को डेट कर रहीं हैं अनन्या पांडे

हाल ही में अभिनेत्री अनन्या पांडे भी एकेडमी म्यूजियम गाला 2026 में शामिल हुईं, जहां न अपने लुक से छा गई थीं। अब अनन्या ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद एक बार एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने फैंस को अपनी छुट्टियों की एक झलक दिखाई है। उन्होंने अक्षय कुमार और दिवंगल खन्ना के बेटे आरव भाटिया के

साथ एक तस्वीर शेयर की है। अनन्या ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की, जिसमें दोनों घर पर बनी कुछ खाने की चीजों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि बॉलीवुड के मशहूर परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आरव भाटिया लाइमलाइट से दूर रहते हैं।



डायरेक्टर श्री कार्तिक की अगली फिल्म में नजर आएंगी रुक्मिणी वसंत

फिल्म ‘कांतारा: चेप्टर 1’ में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आएंगी। शुक्रवार को फिल्म के मेकर्स ने रुक्मिणी का अपनी टीम में स्वागत करते हुए उनके किरदार की जानकारी दी। वह डायरेक्टर श्री कार्तिक की अगली फिल्म में थारा का किरदार निभाएंगी। अभी फिल्म के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस फिल्म में रुक्मिणी लीड रोल में होंगी और उनके साथ देव रामनाथ और विनायक वैथियानाथन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। डायरेक्टर श्री कार्तिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘ईश्वर के आशीर्वाद से बेहद टैलेंटेड कलाकार रुक्मिणी के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूँ। एक मजेदार, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली फिल्म आने वाली है।’ ओके ओके जीवितम’ की तरह यह फिल्म भी हमेशा आपके दिलों में रहेगी।’’ उन्होंने पोस्ट में रुक्मिणी को टैग करते हुए फिल्म को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। यह पहली

बार होगा जब रुक्मिणी वसंत और डायरेक्टर श्री कार्तिक किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। फिल्म का निर्माण मैडबॉयज एंटरटेनमेंट और सिरुनी सिने कॉर्पोरेशन मिलकर कर रहे हैं, जबकि साईकृष्णा गडवाल इसके को-प्रोड्यूसर हैं। इससे पहले श्री कार्तिक फिल्म ‘कानम’ के जरिए चर्चा में आए थे। इस फिल्म में टाइम ट्रैवल जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट को मां और बेटे के भावनात्मक रिश्ते के साथ जोड़ा गया था। अब वह एक नए प्रोजेक्ट के साथ लौट रहे हैं, जिसमें अलग-अलग कलाकारों और क्रिएटिव टीम के साथ एक नई कहानी पेश करने की तैयारी है। मेकर्स ने रुक्मिणी के किरदार थारा का परिचय एक अनाउसमेंट वीडियो के जरिए कराया। इस वीडियो में श्री कार्तिक, देव रामनाथ और विनायक वैथियानाथन थारा के किरदार को फाइनल करने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसी बीच अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, जो तीनों को चौंका देता है। इसके बाद रुक्मिणी वसंत की एंट्री होती है और दर्शकों को उनके किरदार की पहली झलक देखने को मिलती है।



शिल्पा राव को मिला ‘ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन’ का साथ

सिंगर शिल्पा राव का कॉन्सर्ट विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में ‘ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन’ की एंट्री हुई है। एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है। इसमें ‘बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट’ (बीएमपी) के दौरान शिल्पा राव की परफॉर्मेंस को अचानक रोकें जाने का जिक्र करते हुए इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया है। शनिवार को मुंबई में ‘बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट’ के इवेंट में शिल्पा राव मंच पर लाइव परफॉर्म कर रही थीं, तभी आयोजकों ने जबरन उनका माइक्रोफोन और लाइट बंद कर दीं। वह कुछ देर तक मंच पर ही रहीं। माइक बंद होने के बाद, उनकी जगह ‘कुतले खान प्रोजेक्ट’ के कलाकार कुतले खान को गाने का मौका दे दिया गया। उन्होंने शिल्पा राव के कुछ कहने के दौरान ही गाना शुरू कर दिया।

क्या बोला एसोसिएशन
इस मामले पर एसोसिएशन ने कहा ‘किसी कलाकार की परफॉर्मेंस के बीच में ही जबरन साउंड और लाइट बंद कर देना और फिर मंच किसी और को सौंप देना, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। शिल्पा राव एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और भारतीय संगीत जगत की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक हैं। उनके गानों को पूरे देश में बहुत पसंद किया गया है।’ दृष्टव्य ‘बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट’ की

तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पा राव को मंच पर लाइव परफॉर्म करते समय अपमानित किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करता है। किसी कलाकार के साथ ऐसा बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

एसोसिएशन ने सिंगर का समर्थन करने की कहा

एसोसिएशन ने आगे कहा एआईसीडब्ल्यूए पूरी मजबूती से शिल्पा राव के साथ खड़ा है। अगर वह ‘बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट’ के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहती हैं, तो एसोसिएशन हर कानूनी रास्ते से उनका समर्थन करेगा। भविष्य में अगर किसी कलाकार के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो एसोसिएशन कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। किसी कलाकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

आयोजकों ने मांगी माफी

इससे पहले ‘बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट’ (बीएमपी) के आयोजकों ने सिंगर शिल्पा राव के माइक बंद वाले मामले पर माफी मांगी थी। 24 अक्टूबर को मुंबई में हुए फेस्टिवल में गायिका शिल्पा राव की परफॉर्मेंस को अचानक बीच में ही रोक दिया गया था। इस घटना की फेस्टिवल में आए फैंस ने आलोचना की। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शिल्पा राव ट्रेंड करने लगा।

नितिन नवीन ने राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की बैठक

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। इसमें संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और सुनील बंसल समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले बुधवार को नितिन नवीन ने भाजपा के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत दिल्ली के चांदनी चौक में एक मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च ऐसे समय में निकाला गया, जब एसआईआर को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं।

राउत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मांगी माफी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर टिप्पणी करना शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को भारी पड़ गया। अवमानना की कार्यवाही शुरू होने के बाद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उनका न्यायपालिका की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकार को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कोर्ट उनके माफीनामे पर क्या रुख अपनाती है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने माफी को लेकर एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में संजय राउत ने अपनी माफी को बिना शर्त, बिना किसी योग्यता या शर्त के और स्वेच्छा से दी गई माफी बताया है। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि वह इस माननीय अदालत की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकार को बनाए रखने के महत्व को पूरी तरह समझते हैं।

कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर बात सही दिशा में

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने 29 अक्टूबर को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में पार्टी की आगामी बड़ी रैली के मद्देनजर यह निरीक्षण किया गया। गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कथित कोशिशों के बावजूद, इसमें 10 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। व्यवस्थाओं पर चर्चा के दौरान, गौतम ने विपक्ष के भीतर मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के शीर्ष नेतृत्व को लगभग 190 से 200 सीटों की एक सूची सौंपी गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही एक सम्मानजनक समझौता तय हो जाएगा। गौतम ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों को यहाँ आने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।

हाई कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दी जमानत

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित दो पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद, दोनों नेता इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने उनकी उस अर्जी को मंजूर कर लिया, जिसमें सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब उनके जेल से बाहर आने की संभावना है। इससे पहले, 15 अक्टूबर को कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन.आई. जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट अनूप त्रिवेदी और परितोष कुमार मालवीय पेश हुए थे।

एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के वलीन स्वीप पर भाजपा ने कसा तंज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों में कांग्रेस के पूरी तरह से सफाया होने पर पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक भी सीट न जीत पाना, शिक्षित मतदाताओं की ओर से कांग्रेस-मुक्त भारत के लिए एक स्पष्ट जनादेश है। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए, चौधरी ने जोर देकर कहा कि एमएलसी चुनावों में मतदान का यह निर्णायक रुख एक साफ राजनीतिक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि देश भर के शिक्षित मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया है और भाजपा के शासन मॉडल पर अपना भरोसा फिर से जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य की राजधानी के प्रस्तावित दौरे से पहले, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं का यह फैसला एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देता है। एमएलसी चुनाव के नतीजों का आकलन करते हुए चौधरी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलना और पढ़े-लिखे वर्ग का वोट देना, एक साफ संदेश है—कांग्रेस-मुक्त भारत का संदेश।

मिशन 2027 से पहले यूपी भाजपा की चुनावी रणनीति तय करेंगे अमित शाह

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में कई संगठनात्मक बैठकें कर सकते हैं। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर रही है, जिसमें चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपनी रणनीति को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले शाह, पार्टी के छह संगठनात्मक क्षेत्रों — पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर — में बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और राजनीतिक रूप से अहम इस राज्य के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने पर जोर दिया जाएगा।

ये प्रस्तावित बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब बीजेपी विधानसभा चुनावों से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री



कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान संगठनात्मक और राज्य से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया मांगेंगे। सूत्रों ने बताया कि शाह राज्य में आगामी चुनावी मुकाबले के लिए कार्यकर्ताओं के साथ सुझाव साझा करेंगे। वे गठबंधन सहयोगियों के साथ वार्ता से पहले वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ सीट बंटवारे के फार्मूले पर भी चर्चा करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के भी दो दिवसीय बैठक में शामिल होने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

और बुजेश पाठक तथा राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। भाजपा ने सोमवार को अपनी पुनर्गठित राज्य कार्यकारी समिति की घोषणा की, जिसमें 712 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 548 कार्यकारी समिति सदस्य, 134 विशेष आमंत्रित और 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री तथा लखनऊ से लोकसभा सांसद राजनाथ सिंह स्थायी आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं।

पार्टी हाल के घटनाक्रमों के राजनीतिक असर का भी आकलन कर सकती है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा विवाद भी शामिल है। पटना में, जब वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा, मोदी कहीं नहीं जाएंगे तो खड़गे ने गुस्से में पलटवार करते हुए कहा, मोदी का बाप भी जाएगा।

एमएलसी चुनावों में कांग्रेस की हार पर जेडीयू ने कसा तंज

पटना। जेडी (यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने गुरुवार को हाल ही में हुए एमएलसी चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से हुए इन चुनावों में मतदाताओं ने विपक्षी पार्टी को नकार दिया है। झा ने कहा कि चार राज्यों की 28 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से एनडीए ने 16 सीटें जीतीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे, तो कांग्रेस अपने प्रदर्शन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी?

झा ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। 28 सीटों पर चुनाव हुए और एनडीए ने 16 सीटें जीतीं; सभी जानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ। पीएम मोदी

ये किसी एक दल का आंदोलन नहीं

राहुल ने की वोट चोरी के खिलाफ मार्च में जुटने की अपील

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोगों से 1 नवंबर को चलो दिल्ली रामलीला मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वे शामिल हो। उन्होंने इसे लोकतंत्र को बचाने, वोट की चोरी रोकने और संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन बताया।

एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा किए गए वीडियो संदेश में, राहुल गांधी ने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य वोट की चोरी को रोकना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है।

उन्होंने कहा, चलो दिल्ली रामलीला मार्च। यह लोकतंत्र को बचाने, वोटों की चोरी रोकने और संविधान को बचाने के लिए एक मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक दल का मार्च नहीं है। यह भारत की आत्मा का मार्च है। वे सभी लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से तंग आ चुके हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। आप सभी आएँ।

राहुल गांधी ने लोगों से पुलिस की कार्रवाई से न डरने की अपील करते हुए कहा, पुलिस की चिंता न करें, लाडियों की



परवाह न करें। भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपनी कोई चाल चल सकें। आइए, हमारे साथ मार्च में शामिल हों। हम संविधान और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह देश का मार्च है, यह आपका मार्च है। आप सभी आएँ; हम सब मिलकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।

राहुल गांधी ने अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले छात्र समूहों से भी इस मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं सभी छात्र समूहों से अपील करता हूँ। चाहे आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। अगर आपको लगता है कि भारत पर हमला हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पर, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचारों और आपकी सोच के तरीके पर हमला हो रहा है, तो आइए और हमारे साथ जुड़िए। यह एक शानदार मार्च होगा, और यह इस देश की आत्मा के लिए एक मार्च है। मुझे आप सभी के वहां आने का इंतजार रहेगा।

एमएलसी चुनाव परिणाम : अपने प्रदर्शन पर अहंकार न करे भाजपा : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। विपक्ष की तरफ से 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन महाभियोग और 1 नवंबर को दिल्ली में रैली करने की योजना है। इसी बीच आज तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर बैठक भी की है। वहीं, पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कई मुद्दों पर बातचीत की है।

इस दौरान कर्नाटक में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर खरगे ने कहा- हम अभी भी बैलेट पेपर (मतपत्र) का मांग करते हैं। सिर्फ इसलिए कि वे जीत रहे हैं, हमें मैदान नहीं छोड़ देना चाहिए। एक समय ऐसा भी था

जब वे संसद की केवल दो सीटें जीते थे... कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी की कोई पकड़ नहीं है। भाजपा को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर ऐसा है, तो वे संसद को भंग कर दें और बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें।

उन्होंने आगे कहा- हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है क्योंकि वोट चोरी हुई है और (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आयोग में एक गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आगे भी जारी रहेगा और सभी पार्टियां हमारा समर्थन कर रही



हैं। शुक्रवार को एक मॉक पार्लियामेंट (प्रतीकात्मक संसद) है और 1 नवंबर को हम एक रैली कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हम लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक आप संघर्ष नहीं करते, तब तक लोग जागरूक नहीं होते। इसलिए हम यह सब कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ

प्रस्तावित ‘जनता का महाभियोग’ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आवास पर बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड़ा, केशी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, गौरव गोगोई, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओ’ब्रायन और जॉन ब्रिटान समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए।

सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम को संसद की कार्यवाही की तरह आयोजित करने की तैयारी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तर्ज पर सांसद अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम में करीब 40 वक्ताओं के

शामिल होने की संभावना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की संबोधित कर सकते हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका कौन निभाएगा, इस पर भी फैसला लिया जाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे खरगे के आवास पर आयोजित होगा।

स्टोल प्रमुख समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज

ऑकलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 12:30 बजे

शुरू होगा। भारत की नजरें सीरीज में लगातार चौथी जीत दर्ज करने पर होगी, जबकि न्यूजीलैंड घरेलू मैदान पर जीत के साथ वापसी करना चाहेगा।

शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अब प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है। ऐसे में स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलने की उम्मीद है। वहीं, ईशान किशन की फिटनेस और तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को चौथे टी20 मुकाबले में खेलने का अवसर मिल सकता है। दोनों खिलाड़ियों को हाल के महीनों में नियमित मौके नहीं मिले हैं। वरुण का पिछले छह महीनों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जबकि कुलदीप ने मध्य ओवरों में विकेट लेने की अपनी क्षमता दिखाई है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वेल्सिंगटन में पिछले मुकाबले के डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की और अंतिम ओवर में लगातार यॉर्कर डाले। हालांकि, शुरुआती तीन मैचों में उन्होंने 72 गेंदों पर 139 रन खर्च किए हैं। चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे भुवनेश्वर को अपनी इकॉनमी में सुधार करना होगा। पिछले दो मुकाबलों में मध्य यादव को जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। अब चौथे टी20 में टीम प्रबंधन के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। मयंक को वापसी का मौका मिलता है या टीम प्रिंस पर ही भरोसा जताती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 905 अंक बढ़ा, निफ्टी 22900 के पार पहुंचा

नई दिल्ली। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सेंसेक्स 905.01 अंक उछलकर 74,151.04 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 237.91 अंक की बढ़त के साथ 22,936.75 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों को करीब पांच लाख करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान है। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में पांच फीसदी का उछाल आया। कोटक बैंक के शेयर भी चार फीसदी चढ़ गए। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क रखा। बाजार में अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक बढ़ती देखी गई। बाजार में तेजी के पीछे छह प्रमुख कारण रहे। पहला, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। दूसरा, लॉग टर्म कैपिटल गेन कर में कटौती की उम्मीदें बढ़ीं।

5 नई डीजल एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है महिंद्रा

नई दिल्ली। स्वदेशी कंपनी महिंद्रा आने वाले समय में 5 नई डीजल एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इन एसयूवी में नई विजन एस, थार रॉक्स फेसलिफ्ट, स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट, स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप शामिल हैं। कुछ मॉडल इस साल के आखिर तक आ सकते हैं, जबकि स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को अप्रैल 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इन गाड़ियों में नए डिजाइन से लेकर बेहतर फीचर्स तक देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा विजन एस कंपनी की नई छोटी एसयूवी होगी, जिसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसका डिजाइन बॉक्सी होगा और इसमें चौकोर एलईडी हेडलैंप, नई ग्रिल और बड़े व्हील आर्च मिल सकते हैं। इसमें थार और थार रॉक्स वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है।



में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इससे शाकाहारी थाली की कीमत 4 प्रतिशत बढ़कर 31.3 रुपए तथा मांसाहारी थाली 4 प्रतिशत बढ़कर 59.5 रुपए मूल्य की हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो, कमजोर उष्ण, आपूर्ति बाधाओं और भू-राजनीतिक तनावों ने देश में खाद्य स्थिति को कठिन बना दिया है। ऐसे में लोकल सफ़िफ़्स के द्वारा प्रकाशित मूड ऑफ़ द कंज्यूमर्स सर्वे अक्टूबर 2026 बता रहा है कि त्योहार के दिनों में आम आदमी महंगाई को लेकर चिंता के कारण गैरजरूरी खरीदारी में सावधानी बरत रहा है। इस समय उपभोक्ताओं के सामने वे रिपोर्टें भी हैं, जो बता रही हैं कि आगामी

सुजुकी ने 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें भेजीं विदेश

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक व्हीलर के ग्लोबल मार्केट में एक नया कीर्तिनाम स्थापित किया है। कंपनी ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2025 में वैश्विक शिपमेंट शुरू होने के बाद से लेकर अक्टूबर 2026 तक उसने कुल 50,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात कर लिया है। मारुति सुजुकी की इस बड़ी कामयाबी ने वैश्विक स्तर पर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की साख को काफी मजबूत किया है। घरेलू बाजार में दमदबा बनाने के बाद मारुति सुजुकी अब भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों को विदेशी बाजारों में पहुंचाने में भी सबसे आगे निकल गई है। कंपनी ने आंकड़ों के मुताबिक, चांगू वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल से सितंबर के बीच भारत से निर्यात किए गए कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में अकेले मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 93 प्रतिशत रही है।

हुंडई की नई जेनेरेशन क्रेटा की टेस्टिंग शुरु

नई दिल्ली। अपनी नई जेनेरेशन क्रेटा की हुंडई कंपनी ने टेस्टिंग शुरु कर दी है। कई बड़े बदलाव के साथ हुंडई बाजार में लाने की तैयारी में है। जानकारों के अनुसार, नई जेनेरेशन क्रेटा में पांच ऐसे नए फीचर्स मिल सकते हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाएंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव बड़ी इन्फोटेनेमेंट टचस्क्रीन के तौर पर देखने को मिल सकता है। इसमें हुंडई का नया पीएलईओएस इन्फोटेनेमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जिसकी स्क्रीन 15 इंच से भी बड़ी हो सकती है। इस सिस्टम में ओवर-द-एयर अपडेट भी मिलेगा, जिससे गाड़ी के सॉफ्टवेयर को बिना सर्विस सेंटर विजिट किए अपडेट किया जा सकेगा। दूसरा प्रमुख फीचर उन्नत अड्यास (एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम) होगा।

त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई की चुनौती, वस्तुओं की कीमतों में उछाल की चुनौती

डॉ जयंती लाल भण्डारी

इन दिनों दीपावली के त्योहारी सीजन में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल से निम्न और मध्यमवर्गीय परिवार महंगाई की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हालांकि फिर भी दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में महंगाई नियंत्रित बनी हुई है। वैश्विक बाजार असुसंधान एजेंसी इम्पेस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां वैश्विक स्तर पर अधिकांश लोग महंगाई को अपनी सबसे बड़ी चिंता मानते हैं, वहीं भारत में यह आंकड़ा महज 24 प्रतिशत के स्तर पर है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से रक्षावर्ती और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने अपने घरेलू बाजार में कीमतों को संतुलित रखने में सफलता पाई है। लगभग 79 प्रतिशत भारतीयों ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को सकारात्मक बताया है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत के साथ 23 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो अगस्त में 4.83 प्रतिशत थी। इसी तरह सितंबर 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई है, जो अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी। महंगाई में इस उछाल का मुख्य कारण ईंधन, बिजली, खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की बढ़ती कीमतें हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रकाशित क्रिसिल की ‘रोटी राइस रेट’ रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की थाली महंगी हो गई है। सितंबर माह में प्याज की कीमतों में 34 प्रतिशत, खाद्य तेलों में 12 प्रतिशत, एलपीजी में 10 प्रतिशत और चावल



महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत में अल नीनो के प्रभावों और कम बारिश के कारण भी आगामी महीनों में महंगाई के बढ़ने की आशंका है। वर्तमान में देश के लगभग 38 प्रतिशत क्षेत्र तथा आधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसूनी बारिश की कमी काफ़ी चिंता है। रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो, कमजोर उष्ण, आपूर्ति बाधाओं और भू-राजनीतिक तनावों ने देश में खाद्य स्थिति को कठिन बना दिया है। ऐसे में लोकल सफ़िफ़्स के द्वारा प्रकाशित मूड ऑफ़ द कंज्यूमर्स सर्वे अक्टूबर 2026 बता रहा है कि त्योहार के दिनों में आम आदमी महंगाई को लेकर चिंता के कारण गैरजरूरी खरीदारी में सावधानी बरत रहा है। इस समय उपभोक्ताओं के सामने वे रिपोर्टें भी हैं, जो बता रही हैं कि आगामी

उपाय है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इसमें बढ़ोत्तरी होते ही बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से फंड लेना महंगा हो जाता है। बैंक अपनी लागत की भरपाई के लिए होम, कार और अन्य कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, जिससे ग्राहकों की ईएमआई बढ़ जाती है। कर्ज महंगे होने से आम लोग और उद्यमी-कारोबारी कम कर्ज लेते हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाने के साथ 9 अक्टूबर को नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) के न्यूनतम दैनिक रखरखाव की आवश्यकता 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दी है। पहले बैंकों को यह छूट प्राप्त थी कि वे 14 दिनों के दौरान किसी दिन अपने आवश्यक सीआरआर का न्यूनतम 90 प्रतिशत हिस्सा रखकर शेष दिनों में संतुलन बना सकते थे। अब रोजाना 99 प्रतिशत हिस्सा नकद में रखना अनिवार्य होने से बैंकों की दैनिक लचीलापन की स्थिति समाप्त हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उनकी आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण

बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा, संगठन और सामाजिक चेतना के माध्यम से दिखाई प्रगति की राह : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से सरगुजा अंचल में आयोजित जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रख्यात अभियंता एवं पूर्व सांसद बाबा कार्तिक उरांव के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल होकर उनकी भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नामकरण ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का जीवन शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक चेतना और जनजातीय समाज के स्वाभिमान की प्रेरक गाथा है। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।



मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सीतापुर क्षेत्र को अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण सीमागत देते हुए सोनतराई से सूर तक लगभग 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के निर्माण पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इसके निर्माण से सीतापुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा तथा व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नवनिर्मित महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन नवीन भवनों से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को

सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव केवल जनजातीय समाज के महान नेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, उच्च शिक्षित अभियंता और समाज के अधिकारों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता, संगठन और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जब जनजातीय समाज के लिए शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और विदेश में भी उच्च अध्ययन कर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। उनकी यह उपलब्धि पूरे जनजातीय समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

ग्रामीण पत्रकारिता को मिलेगी नई पहचान

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दो विवि के बीच हुआ एमओयू

संयुक्त शोध, प्रशिक्षण, इंटरशिप और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जमीनी पत्रकारिता को मिलेगा बढ़ावा



रायपुर। ग्रामीण अंचलों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और युवाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर और गोंडवाना विश्वविद्यालय, गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) के बीच ग्रामीण पत्रकारिता को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में पत्रकारिता शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दयाल ने कहा कि भारत की

आत्मा गांवों में बसती है और ग्रामीण पत्रकारिता ही जमीनी वास्तविकताओं को समाज के सामने लाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों के साझा प्रयासों से ऐसे पत्रकार तैयार किए जाएंगे, जो संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों के साथ ग्रामीण विकास, स्थानीय समस्याओं तथा जनजीवन से जुड़े विषयों को प्रमुखता से सामने लाएंगे।

गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रशांत बोकारे ने इस समझौते को ग्रामीण पत्रकारिता के संवर्धन और उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने

कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।

समझौता ज्ञापन पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा तथा गोंडवाना विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद सरफराज अंसारी ने हस्ताक्षर किए। एमओयू के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से संगोष्ठियों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। ये गतिविधियाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड माध्यमों से संचालित होंगी।

करवा चौथ प्रेम, विश्वास, समर्पण और पति-पत्नी के अटूट रिश्ते का प्रतीक : सुखबीर सिंह सिंघोत्रा

रायपुर। करवा चौथ के पावन पर्व पर राजधानी रायपुर के शंकर नगर क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं धार्मिक श्रद्धा के साथ करवा चौथ की पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने करवा चौथ की कथा सुनी, करवा माता की पूजा की तथा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की मंगलकामना की। पूजा-अर्चना के उपरांत महिलाओं ने एक-दूसरे को करवा चौथ व्रत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने बताया कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं



से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, निष्ठा, त्याग और समर्पण का भावना को दर्शाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु एवं सुखी दांपत्य जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं सुबह 4 बजे से उठकर स्नान के बाद पूजा कर व्रत की शुरुआत करती हैं

और यह व्रत निर्जला व्रत होता है दिन भर सुहागन पानी तक ग्रहण नहीं करती और शाम को एक साथ एकत्रित होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करती हैं उन्होंने बताया कि करवा चौथ पर महिलाओं द्वारा पूजा की थालियों का आपस में आदान-प्रदान करने की परंपरा को ‘करवरा वटना’ कहा जाता है।

रायपुर में आज मनेगा पीएम किसान उत्सव दिवस

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानन्द ऑडिटोरियम (कृषि महाविद्यालय परिसर) में सुबह 10 बजे से राज्य स्तरीय पीएम. किसान उत्सव दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बनासकांठा से ऑनलाइन माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 24 लाख 60 हजार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 498 करोड़ 48 लाख रुपये उनके खातों में अंतरित की जाएगी।

वित्त मंत्री ने राज्योत्सव की तैयारियों का किया निरीक्षण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित आगमन को लेकर आयोजन स्थलों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में राज्योत्सव 2026 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रस्तावित आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थित सत्य साईं हॉस्पिटल, विकसित भारत संकल्प पार्क (पीपल वन) तथा तूता गांव क्षेत्र का दौरा कर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आयोजन को भव्य,



सुव्यवस्थित, सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली परंपराओं और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का प्रस्तावित आगमन

विशेष महत्व रखता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां आपसी समन्वय के साथ समय-सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नवा रायपुर के विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर चल

रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने आयोजन स्थलों की साफ-सफाई, आवागमन, पार्किंग, सुरक्षा तथा आगंतुकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम स्थलों पर नागरिकों के सुगम आवागमन और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्योत्सव प्रदर्शवासीयों के लिए गौरव और उत्साह का अवसर है। ऐसे में आयोजन की प्रत्येक व्यवस्था सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

अंधविश्वास के कारण भी प्रताड़ना व मानवाधिकार हनन : डॉ. मिश्र

रायपुर। प्रदेश के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ एवं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने यूनाइटेड नेशंस, जिनेवा में कहा कि संसार के अनेक देशों से अंधविश्वास के कारण महिलाओ के साथ प्रताड़ना की घटनाएं घटती है और उनके मानवाधिकार हनन के मामले सामने आते है, जो चिंतनीय है। अविक्सित और विकासशील देशों से ऐसी घटनाओ की खबरें अधिक हैं। डॉ. दिनेश मिश्र ने डायन प्रताडना और मानवाधिकार (विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि महिला प्रताडना और उनके मानवाधिकार हनन के कारणों में एक प्रमुख कारण अंधविश्वास और डायन के संदेह में प्रताडना भी है जो एशिया के देशों, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफ्रीका के अनेक देशों में जारी है। उनके पास एशिया सहित दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा अनेक देशों में घटित घटनाओं के आंकड़े हैऔर मामलों की जानकारी है जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर किये जाने वाले दावों और वास्तविकता स्थिति के संबंध भिन्नता बताती है। महिला प्रताडना के मामलों में तो उन्हें मानव या ईसानी ही नही समझा जाता तो उन्हें मानव अधिकार देने के दावे झुठे साबित हो जाते है। अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और ,वैज्ञानिक जागरूकता की कमी ,गैर जरूरी,परंपराओं को आख मूंद कर पालन करने की आदत से न ही अंधविश्वास खत्म हो पाते हैं।

भाजपा का लोकतंत्र बचाओ अभियान ज्ञानेश को बचाने के लिए : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा द्वारा वोट चोरी के समर्थन में लोकतंत्र बचाओ अभियान वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के मतदाता अपने मतदान के अधिकार की चोरी के खिलाफ लामबंद है। युवा, छात्र, विपक्षी दल, आम आदमी सभी एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी के खिलाफ एकजुटता से खड़े है। प्रदेश भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन के खिलाफ पूरे देश में वातावरण इससे घबरा कर भाजपा लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने जा रही है। भाजपा देश के मतदाताओं और नागरिकों को भीड़ तंत्र बताने का दुस्साहस कर रही है। इसी भीड़ तंत्र से भारत का लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का अभियान चोरी ऊपर से सीनाजोरी है। जब वोट चोरी का षडयंत्र रहे हाथों पकड़ा गया, तो भाजपा ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए मैदान में उतर आई। यह साबित करता है कि यह प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि भाजपा का प्रायोजित वोटर डिलीटी सिंडिकेट है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के दिए सवैधानिक अधिकारों पर भाजपा सरकार ने डाका डालना शुरू कर दिया है।

रायपुर कमिश्नरेट में बदलाव : इंस्पेक्टर समेत 30 पुलिसकर्मियों का तबादला

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव हुआ है। बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से आदेश के अनुसार, निरीक्षक मनीष तिवारी को रक्षित केंद्र रायपुर से हटाकर यातायात पुलिस कमिश्नरेट में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। इस संबंध में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने आदेश जारी कर दिये हैं। इस ट्रांसफर के तहत विभिन्न थानों, रक्षित केंद्र, महिला थाना, यातायात शाखा और पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थापना दी गई है। वहीं 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें उप निरीक्षक, हवलदार और सिपाही स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। जारी आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों और रक्षित निरीक्षक को रवानगी एवं आमद की सूचना पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय को देने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री हेलपलाइन से समस्या का हल नही केवल खानापूति : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री हेलपलाइन में बैठे लोगों द्वारा मिलने वाली शिकायतों को केवल समस्याओं को संबन्धित विभाग में रेफर कर देने को समाधान बता कर खानापूति की जा रही है। सरकार इसी में अपनी पीठ थपथपा रही है। भाजपा सरकार जब से बनी है राजनैतिक प्रचार और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जतन मात्र करती है उसे जनता की समस्याओं के निराकरण से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में भी हर गुरुवार को जनता से मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ढाई साल में आधा दर्जन गुरुवार को भी मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिले। भाजपा सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों को नियमित बैठने की घोषणा किया वह भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री हेलपलाइन भी बहुत जल्दी उबाऊ कॉल सेंटर में तब्दील होगा फिर बंद हो जायेगा। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 के बीच मुख्यमंत्री हेलपलाइन 1076 पर कुल 2,31,850 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 2,05,996 शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी गई, जबकि 25,854 शिकायतें लंबित थीं।

जनजातीय अंचलों में पर्यटन से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में होम-स्टे और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों, युवाओं और महिला समूहों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नई उद्योग नीति एवं होमस्टे नीति के तहत बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और ग्रामीण जीवनशैली को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई), नवा रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितवाहियों को होम-स्टे संचालन के माध्यम से आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति बैठक संपन्न

राज्य की महत्वाकांक्षी अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं की हुई समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में अधोसंरचना विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित कई प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि

निवेशकों को बेहतर वातावरण मिले और राज्य के विकास को गति प्राप्त हो सके। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए निविदा शर्तों तथा रियायत समझौते के संशोधित प्रावधानों

पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अनुभवी डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। ट्रांसपोर्ट नगर बिलासपुर में लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर

परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई। रायपुर के पंडरी में कृषि उपज मंडी की भूमि पर स्थापित होने वाले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी भूमि आवंटन शर्तों और प्रावधानों में एकरूपता लाने तथा विकास अवधि के

समन्वय के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।

कमर्शियल टॉवर व फ्लैटेड फैक्ट्री (भिलाई) एवं औद्योगिक क्षेत्र छत्ती धमतरी के संबंध में जानकारी दी गई कि भिलाई में कमर्शियल टॉवर, फ्लैटेड फैक्ट्री की परियोजनाओं को अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा स्वयं विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वार्णिण्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में रायपुर जिले के प्रकरणों की जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी की उपस्थिति में कुल 47 प्रकरणों में से 30 पर सुनवाई हुई। इनमें 10 प्रकरणों का निराकरण कर नस्तीबद्ध किया गया।

जनसुनवाई के दौरान बैंक से संबंधित एक प्रकरण में आवेदिका के पक्ष के समर्थन में बैंक की महिला अधिकारी ने अपना बयान दर्ज कराया। आयोग ने अनावेदक पक्ष को शिकायत का जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के

लिए 15 दिन का समय दिया। आगामी सुनवाई में बैंक की आंतरिक शिकायत समिति से जुड़े अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए।

संपत्ति के बंटवारे और स्वर्गीय पति के होटल व्यवसाय में हिस्सेदारी से जुड़े प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर उनके कथन दर्ज किए गए। आयोग ने मामले को

आगे की सुनवाई के लिए रखा। दिव्यांग आवेदिका से संबंधित प्रकरण में आयोग ने उन्हें काम पर रखने और वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक कदम

उठाने के निर्देश दिए। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र भेजने के लिए भी कहा गया। नाबालिग बच्ची की सुरक्षा से जुड़ी शिकायत पर आयोग ने बाल संरक्षण आयोग को पत्र भेजने और संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित करने का निर्णय लिया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHMHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.